



Alia Bhatt Looks Stunning In...

SHARE	
सेंसेक्स	: 85,267.66
निफ्टी	: 26,046.95

SARAFI	
सोना	: 12,310
चांदी	: 215.00

(नोट : सोना 22 कैरेट प्रति ग्राम)

BRIEF NEWS

विनेश फोगाट ने 2028 के लिए वापस लिया संन्यास

PUNCHKULA : विनेश फोगाट ने संन्यास वापस लेकर कुश्ती में लौटने का फैसला लिया है। वे 2028 में लॉस एंजलिस ओलिंपिक में हिस्सा लेना चाहती हैं। विनेश ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा, 'खामोशी में मुझे कुछ ऐसा मिला जिसे मैं भूल गई थी। आग कभी खत्म नहीं होती।' विनेश 2024 के पेरिस ओलिंपिक में फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय रसलर बनी थी। हालांकि, फाइनल से पहले उनका 100 ग्राम वजन ज्यादा निकला, जिससे वे डिस्क्वालिफाई हो गईं। इसके बाद उन्होंने रसलिंग को अलविदा कह दिया था। विनेश अभी हरियाणा के जुलाना से कांग्रेस विधायक हैं।

16 को समुद्री बेड़े में शामिल होगा 'डीएससी ए-20'

NEW DELHI : भारतीय नौसेना के समुद्री बेड़े में 16 दिसंबर को गोताखोरी में सहायक स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित जहाज 'डीएससी ए-20' को शामिल किया जाएगा। दक्षिणी कमान का हिस्सा बनने वाले इस जहाज का कमीशनिंग समारोह कोच्चि में होगा, जो नौसेना के लिए बड़ी उपलब्धि है। इसके माध्यम से भारतीय नौसेना की गोताखोरी और जल के भीतर सहायता क्षमताओं में तेजी आएगी। दक्षिणी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ वाइस एडमिरल समीर सक्सेना की उपस्थिति में आयोजित होने वाला यह औपचारिक समारोह नौसेना की परिवर्तन क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण वृद्धि का प्रतीक होगा। डीएससी ए20 का निर्माण कोलकाता के टिट्टागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड (टीआरएसएल) में किया गया है। गोताखोरी में सहायक पांच ड्राइंग रूमों का ट्रायल चालू किया जा रहा है। इसको तटीय जलक्षेत्र में विभिन्न प्रकार के गोताखोरी और जलयान अभियानों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है।

आंध्र प्रदेश में बस घाटी में गिरी, नौ यात्रियों की मौत

ALLURI : शुक्रवार को आंध्र प्रदेश के अल्तुरी सीताराम राजू जिला में मारेडुमिली घाट रोड पर बस हादसे में बड़ी जनहानि होने का अंदेश है। घटनास्थल पर नौ लोगों की मृत्यु और अन्य दस के गंभीर रूप से घायल होने की पुष्टि हुई है। मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। बताया गया है कि हादसाग्रस्त चित्तूर जिले के विनेश्वर टाटवली की बस (एपी 39 यूएम 6543) में 37 यात्री और दो चालक थे। यह बस भद्रावल्लु से अरकूट जा रही थी। मारेडुमिली घाट रोड पर राजू गारी मेट्टु मोड़ के पास यह बस बेकाबू होकर घाटी में गिर गई। सुचना मिलते ही आसपास के लोग पहुंचे और बचाव अभियान शुरू किया। घायलों को बेतरह इलाज के लिए भद्रावल्लु परिव्या हॉस्पिटल ले जाया गया। लोगों का कहना है कि यह बस छह दिसंबर की रात नौ बजे तीर्थयात्रा के लिए निकली थी।

वैभव सूर्यवंशी ने 14 सिक्स लगाकर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

AGENCY NEW DELHI : शुक्रवार को वैभव सूर्यवंशी ने यूएई के खिलाफ 14 सिक्स लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। उन्होंने दुबई में खेले गए यू-19 एशिया कप मैच में 95 गेंदों पर 171 रन बना दिए। इस पारी में वैभव ने 14 छक्के और 9 चौके के सहारे 180 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की। इसी के साथ वे यूथ वनडे में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाले बल्लेबाज बन गए। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के माइकल हिल का 2008 में बना 12 सिक्स वाला रिकॉर्ड तोड़ दिया। 14 साल के वैभव ने महज 56 गेंदों में सेंचुरी पूरी की। उनकी बैटिंग के दम पर भारत ने यूथ वनडे में अपना सबसे बड़ा स्कोर खड़ा किया। टीम ने 433 रन बनाए, जो पिछले साल ढाका द्वारा स्कॉटलैंड के खिलाफ बनाए 425 रन के रिकॉर्ड से ज्यादा है। वैभव के साथ एरोन जॉर्ज और विहान मल्होत्रा ने भी 69-69 रन की अहम पारियां खेलीं।



दुबई में खेले गए यू-19 एशिया कप मैच में 95 गेंदों पर बना दिए 171 रन

वैभव ने 9 चौके भी जड़े, 180 के स्ट्राइक रेट से की बैटिंग, महज 56 गेंदों में पूरी की सेंचुरी

मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी शतक लगाने वाले यंगेस्ट बैटर हैं वैभव

वैभव ने 10 दिन पहले सेयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी शतक लगाया था। 14 साल के वैभव टूर्नामेंट में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने थे। उन्होंने 2 दिसंबर को इंडन गार्डन्स में महाराष्ट्र के खिलाफ 61 गेंदों में नाबाद 108 रन बनाए, जिसमें 7 चौके और 7 छक्के शामिल थे। साथ ही वैभव 14 की उम्र में 3 टी-20 सेंचुरी लगाने वाले इकलौते प्लेयर हैं। वैभव सूर्यवंशी आईपीएल में फिफ्टी लगाने वाले सबसे कम उम्र के प्लेयर बने। उन्होंने मात्र 14 साल और 32 दिन में अर्धशतक लगाया। सेकेंड पोजिशन पर कप्तान रियाज पराग हैं, उन्होंने 17 साल 175 दिन में 2019 में फिफ्टी लगाई थी।

8 फर्स्ट क्लास मुकाबले खेले 18 टी-20 में भी 701 रन दर्ज

टी-20 क्रिकेट में अब तक के सबसे युवा शतक लगाने वाले खिलाड़ियों में वैभव सूर्यवंशी का नाम सबसे ऊपर आता है। उन्होंने 14 साल 32 दिन की उम्र में राजस्थान रॉयल्स के लिए गुजरात टाइटन्स के खिलाफ 35 बॉल में शतक पूरा किया। इसके बाद, विजय जौल ने 18 साल 118 दिन में महाराष्ट्र के लिए मुंबई के खिलाफ 2013 में शतक लगाया था। वैभव सूर्यवंशी ने बिहार के लिए अबतक 8 फर्स्ट क्लास और 6 लिस्ट-ए मुकाबले खेले हैं। वैभव ने फर्स्ट क्लास मैचों में जहां 207 रन बनाए हैं, तो वहीं लिस्ट में उनके नाम 132 रन दर्ज हैं। उनके नाम 18 टी-20 में 701 रन दर्ज हैं।

क्रिकेट के प्रति लगाव देखकर पिता ने ट्रेनिंग के लिए बेव दी थी जमीन

वैभव सूर्यवंशी बिहार के समस्तीपुर जिले के ताजपुर के रहने वाले हैं। 27 मार्च 2011 को जन्मे वैभव ने 9 साल की उम्र में अपने पिता सजीव के गाइडेंस में क्रिकेट खेलना शुरू किया। अपने बेटे का क्रिकेट के प्रति लगाव देखकर सजीव ने वैभव की ट्रेनिंग के लिए जमीन बेव दी। उन्होंने ज्योतिष क्रिकेट एकेडमी समस्तीपुर से ट्रेनिंग शुरू की। वैभव के कोच के मुताबिक, उनके पिता सजीव उन्हें मैच दिखाने के लिए हर दूसरे दिन 100 किमी दूर ले जाते थे। वैभव जब भी एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करते थे उनके पिता सजीव उनके अलावा सभी 10 साथी खिलाड़ियों के लिए भी टिफिन पैक करके लाते थे, क्योंकि उसके साथी गेंदबाज उसी बॉलिंग करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम देते थे।

1000 करोड़ रुपये की अवैध कफ सिरप खरीद-बिक्री का मामला

रांची सहित 25 ठिकानों पर ईडी की टीम ने की ताबड़तोड़ छापेमारी

PHOTON NEWS RANCHI :

शुक्रवार को एनफॉर्मेट डायरेक्टरेट (ईडी) की टीम ने 1000 करोड़ रुपये के अवैध कफ सिरप की खरीद-बिक्री मामले में झारखंड की राजधानी रांची सहित उत्तर प्रदेश और गुजरात के 25 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। सुबह करीब सात बजे से शुरू हुई छापेमारी में रांची के शैली ट्रेडर्स भी शामिल किया गया। झारखंड में कफ सिरप का कारोबार शैली ट्रेडर्स के माध्यम से होता है। कई वाहनों और सुरक्षा के साथ ईडी की टीम शैली ट्रेडर्स की फैक्ट्री में पहुंची। फैक्ट्री के अंदर जाने के लिए टीम को इंतजार करना पड़ा। ईडी की यह कार्रवाई लखनऊ, बनारस, जौनपुर, सहायपुर और अहमदाबाद में भी हुई। झारखंड की राजधानी रांची के तुपुदना औद्योगिक क्षेत्र स्थित शैली ट्रेडर्स के संचालक भोला प्रसाद के प्रतिष्ठान और उनके फ्लैट में भी ईडी

तुपुदना स्थित फैक्ट्री में जांच टीम को जाने के लिए करनी पड़ी प्रतीक्षा

झारखंड में शैली ट्रेडर्स के माध्यम से होता है कारोबार

संचालक भोला प्रसाद के प्रतिष्ठान और फ्लैट में अधिकारियों ने ली तलाशी, कागजात जप्त

लखनऊ, बनारस, जौनपुर, सहायपुर और अहमदाबाद में भी हुई कार्रवाई



कुछ दिन पहले बनारस पुलिस ने मारी थी रेड

जानकारी के अनुसार, शैली ट्रेडर्स का यह प्रतिष्ठान भोला प्रसाद ने भिलाई कैमिकल के संचालक जगन्नाथ साहू से किराए पर लिया था। कुछ दिनों पहले बनारस पुलिस ने यहां छापेमारी की थी, लेकिन कफ सिरप की बरामदगी किसी अन्य स्थान से हुई थी। तुपुदना औपी में इस मामले में एक दिन पहले औपध निबंधक शैल अबध

मध्य प्रदेश में कई बच्चों की हुई थी मौत

बता दें कि इसी वर्ष मध्य प्रदेश के गुना और विदिशा में सड़िये तौर पर कोडीन और कोल्ट्रिक कफ सिरप पीने के बाद कई बच्चों की मौत और गंभीर बीमारियां सामने आई थीं। इसके बाद पूरे नेटवर्क की जांच शुरू हुई। रिपोर्टों के बाद यह साफ हुआ कि केवल एक जहरीला सिरप ही नहीं, बल्कि बड़े पैमाने पर कोडीन-यूक कफ सिरप की तस्करी का रैकेट चल रहा था, जिसकी सप्लाई मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्यों में हो रही थी। जांच के बाद यह बात सामने आई कि इस नेटवर्क का मास्टरमिण्ड बनारस का शुभम जायसवाल है। जिसने फर्जी फर्मा और नकली बिलिंग के माध्यम से कोडीन कफ सिरप की बड़े पैमाने पर खरीद और अलग-अलग राज्यों व पड़ोसी देशों में सप्लाई की।

शैली ट्रेडर्स ज्ञानलेवा कफ सिरप का सालाना कारोबार पांच करोड़ रुपये से अधिक का है।

केंद्रीय कैबिनेट का फैसला, दो चरणों में होगा सर्वे जनगणना 2027 के लिए 11718 करोड़ रुपये मंजूर

NEW DELHI @ PTI :

शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय कैबिनेट ने जनगणना 2027 के लिए 11718 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। कहा कि जनगणना 2027 दो चरणों में आयोजित की जाएगी। इसके तहत अप्रैल और सितंबर 2026 के बीच घरों की सूची तैयार की जाएगी और फरवरी 2027 में जनगणना की जाएगी। वर्ष 2027 में होने वाली जनगणना

फर्स्ट फेज में अप्रैल और सितंबर 2026 के बीच तैयार की जाएगी घरों की सूची

पहली डिजिटल जनगणना होगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जनगणना 2027 में जाति आधारित गणना को भी शामिल किया जाएगा। वैष्णव बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में जनगणना कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, जो अपनी तरह की पहली डिजिटल जनगणना होगी।

भगदड़ की निष्पक्ष जांच होना जरूरी : सुप्रीम कोर्ट

NEW DELHI :

शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने करुण भगदड़ मामले में पहले दिए गए अपने निर्देश को बल देने से इनकार कर दिया। अदालत ने निर्देश दोहराते हुए कहा कि सीबीआई जांच की निगरानी करने वाले सुपरवाइजरों को केटी के सदस्य तामिलनाडु के मूल निवासी नहीं होंगे। मामले की सुनवाई जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस जियु बिस्नोई की बेंच ने की। विजय की पार्टी टीवीके की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लुथरा ने सीबीआई जांच के आदेश पर आपत्ति जताई थी, लेकिन कोर्ट ने कोई बदलाव नहीं किया। सुनवाई के दौरान जस्टिस महेश्वरी ने कहा, हम चाहते हैं कि सब कुछ निष्पक्ष हो। सुप्रीम कोर्ट ने 13 अक्टूबर के अपने फैसले को याद किया और बताया कि यह केटी जांच को पूरी तरह निष्पक्ष बनाने के लिए बनाई गई थी।

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिरकी ने डीबीटी के जरिए भेजे रुपये 32911 किसानों को मिली 15.63 करोड़ की प्रोत्साहन राशि

PHOTON NEWS RANCHI :

शुक्रवार को हेमंत सरकार ने राज्य के हजारों किसानों को बड़ी राहत दी। मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया गया। राज्य के 32 हजार 911 किसानों के बैंक खातों में 15 करोड़ 63 लाख 24 हजार 900 रुपये की प्रोत्साहन राशि ट्रान्सफर की गई। रांची स्थित पशुपालन निदेशालय सभागार में आयोजित कार्यक्रम में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिरकी ने डीबीटी के जरिये यह राशि ट्रान्सफर की। साथ मंत्री ने घोषणा की कि अब झारखंड मिलेट मिशन को झारखंड महुआ

अब झारखंड महुआ क्रांति के नाम से जाना जाएगा मिलेट मिशन



क्रांति के नाम से जाना जाएगा। मंत्री शिल्पी नेहा तिरकी ने कहा कि गांवों में महुआ की स्वीकार्यता लगातार बढ़ रही है और किसानों की आय में इसका बड़ा योगदान है। पहले राज्य में 20 हजार हेक्टेयर भूमि पर

खेले जाएंगे महुआ अधिप्राप्ति केंद्र

महुआ की खेती अन्य फसलों की तुलना में अधिक मुनाफा देती है। वर्ष 2024-25 में 18 हजार किसानों को प्रोत्साहन राशि का लाभ मिला था। अब विभाग का लक्ष्य 60 हजार किसानों को इसका लाभ देना है। सरकार ने महुआ की खरीदारी के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मंत्री ने बताया कि धान अधिप्राप्ति केंद्र की तर्ज पर महुआ अधिप्राप्ति

केंद्र खोले जाएंगे। पहले चरण में गुमला, रिमडेगा और खुटी जिलों को खिलित किया गया है। इन जिलों के 17 लैस और पैक्स केंद्रों के माध्यम से किसानों से महुआ की खरीद की जाएगी। यह सुविधा अगले एक सप्ताह में शुरू होने की उम्मीद है। महुआ का मूल्य बाजार दर के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।

1980 से 2004 तक सात बार जीता लोकसभा चुनाव नहीं रहे कांग्रेस के दिग्गज नेता व लोस के पूर्व अध्यक्ष शिवराज पाटिल

MUMBAI @ PTI :

शुक्रवार को कांग्रेस के दिग्गज नेता, लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व पूर्व केंद्रीय गृहमंत्री शिवराज पाटिल का निधन लातूर में उनके आवास पर हो गया। 90 वर्षीय पाटिल ने अपने घर पर आंखिरी सांस ली। वह कुछ समय से अस्वस्थ थे। उनके परिवार के एक सदस्य ने यह जानकारी दी। पाटिल ने लोकसभा के 10वें अध्यक्ष के रूप में कार्य किया और सार्वजनिक जीवन में चार दशकों से अधिक समय तक कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे। शिवराज पाटिल का महाराष्ट्र के लातूर जिले के चाकुर गांव में हुआ था। पाटिल ने 1980 में राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश किया। वह



● सार्वजनिक जीवन में चार दशकों से अधिक समय तक संमाले कई महत्वपूर्ण पद

इस साल पहली बार सातवीं लोकसभा के लिए चुने गए और 2004 तक लगातार सात बार लोकसभा का चुनाव जीता। 1980-1990 की अवधि के दौरान उन्होंने संसद सदस्यों के वेंतन और भत्तों पर संयुक्त समिति में कार्य किया।

रणनीतिक कौशल किसी भी प्रकार के दुस्साहस को हर स्तर पर मिलेगा कड़ा जवाब भारतीय जवानों के युद्धाभ्यासों ने दुश्मनों को दिए सख्त संदेश

PHOTON NEWS @ RESEARCH DESK :

इस साल आतंकवाद के खिलाफ मई में ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने के बाद भारतीय सेना के तीनों अंग (थलसेना, नौसेना और वायुसेना) लगातार किसी न किसी सैन्य अभ्यास में अपना युद्ध कौशल निखार रहे हैं। संपूर्ण भारतीय रक्षा प्रणाली को हर स्तर पर मजबूत बनाने की रणनीति पर काम किया जा रहा है। दुश्मनों के किसी भी प्रकार के दुस्साहस को कड़ा जवाब देने की तैयारी है। गौरतलब है कि पाकिस्तान से सटी सीमा पर तीनों सेनाओं के 'त्रिशूल युद्धाभ्यास' के बीच भारत ने पूर्वोत्तर में भी 'नोटिस-टू-एयरमैन' (नोटम) जारी किया है। इसके तहत यहां के हवाई क्षेत्र को नागरिक उड़ानों के लिए अस्थायी रूप से मुक्त रखा गया है। विशेषज्ञों की नजर में सीमा पर दुश्मन देशों के किसी भी कोशिश कोई ना काम करने के लिए इस बार भारत की तैयारी अभूतपूर्व है। भारतीय जवानों के अभ्यासों ने दुश्मनों को सख्त संदेश दिया है। उल्लेखनीय है कि पूर्वोत्तर का इलाका चीन, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश से सटा है।

ऑपरेशन सिंदूर के बाद संपूर्ण प्रतिरक्षा प्रणाली को बनाया जा रहा मजबूत 'त्रिशूल युद्धाभ्यास' के बीच 'नोटिस-टू-एयरमैन' जारी करना बेहद महत्वपूर्ण

● चीन से सटे पूर्वोत्तर में सैन्य अभ्यास के दौरान आसामना को खाली रखने का निर्णय

● 'नोटम' का पहला चरण 6 व 20 नवंबर को पैक्टिस के साथ किया जा चुका है पूरा

● 18 दिसंबर को दूसरा और अगले साल एक व 15 जनवरी को प्रभावी होगा तीसरा चरण

वायुसेना की ऑपरेशनल गतिविधियों को व्यापक बनाने के लिए चाक-चौबंद तैयारी

कई चरणों में चल रहा 'नोटम'

'नोटम' कई चरणों में चल रहा। पहला चरण 6 और 20 नवंबर को पूरा कर लिया गया है। दूसरे चरण का पहला हिस्सा 4 दिसंबर को कर्नाट हो चुका है। 18 दिसंबर दूसरा हिस्सा पूरा होगा। तीसरा चरण अगले साल एक और 15 जनवरी को प्रभावी रहेगा। इस दौरान नागरिक विमान उड़ान नहीं भर सकेंगे, ताकि वायुसेना की ऑपरेशनल गतिविधियों के लिए पूरा आसामना खाली रहे। इन प्रतिरक्षात्मक रूप में देखें तो पूर्वोत्तर का इलाका रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है। यह चार देशों- चीन, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश से घिरा है। अभ्यास के दौरान वायुसेना अपने अग्रिम लड़ाकू विमानों के साथ बड़े पैमाने पर युद्धाभ्यास करेगी। इसका संदेश साफ है कि भारत दुश्मन देशों के किसी भी संभावित दोतरफा दुस्साहस की तैयारी कर रहा है। भू-राजनीतिक नजरिए से देखें तो चीन और बांग्लादेश भारत के अनुकूल वातावरण नहीं रहा है। जाहिर है ये सारे युद्धाभ्यास देश पर कई दिशाओं से आने वाले संकट की सुरत में माकूल जवाब देने की क्षमता परखने और निखारने के लिए है। इस बीच सेना ने राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे रेगिस्तानी इलाकों में बड़े स्तर पर ड्रोन व काउंटर ड्रोन युद्धाभ्यास वायु समन्य-2 किया है। सेना ने बताया कि इस दो दिवसीय अभ्यास में अगली पीढ़ी के युद्ध की तैयारी की गई।

BRIEF NEWS

धनबाद में सैनिक स्कूल खुलने की संभावना बढ़ी



DHANBAD : सांसद दुलु महतो शुक्रवार को केन्द्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ से मिले, जिसमें उनसे धनबाद में सैनिक स्कूल की स्थापना से संबंधित प्रस्ताव दिया। सांसद ने केन्द्रीय राज्य मंत्री को बताया कि धनबाद के युवाओं में देश सेवा के प्रति गहरा उत्साह है। सैनिक स्कूल की स्थापना से उन्हें सुदृढ़ शिक्षा, प्रशिक्षण एवं भविष्य निर्माण का उपयुक्त अवसर मिलेगा। चर्चा के दौरान क्षेत्र की अन्य विकास योजनाओं पर भी संक्षेप में विचार-विमर्श हुआ। सांसद ने बताया कि मंत्री ने सभी विषयों पर सकारात्मक दृष्टिकोण व्यक्त करते हुए आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिया।

रोजगार मेला में 155 युवक-युवतियों का हुआ चयन



LATEHAR : जिला नियोजन कार्यालय ने शुक्रवार को जिला खेल स्टेडियम में एकदिवसीय दत्तोपंत टेंगड़ी रोजगार मेला का आयोजन किया। इसमें लगभग पांच राज्यों के नियोजक विभिन्न पदों के साथ उपस्थित हुए। वहीं, लगभग 1000 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। कंपनियों ने 155 युवक-युवतियों का चयन किया, जबकि 185 युवक-युवतियों को अगले राउंड के लिए शॉर्टलिस्ट किया। विभिन्न नियोजकों द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को विशिष्ट अतिथि एवं जिला नियोजन पदाधिकारी ने ऑफर लेटर प्रदान किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला परिषद की अध्यक्ष सुनीता देवी, उपविभागाध्यक्ष आयुक्त सैयद रिजाल अहमद, विशिष्ट अतिथि विधायक प्रतिनिधि- लातेहार अनिल कुमार सिंह व विधायक प्रतिनिधि- मनिंका हरिशंकर यादव भी उपस्थित थे।

झारखंड के चीफ जस्टिस आज दुमका आएंगे

DUMKA : झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान शनिवार को दुमका आएंगे। वे यहां राज्य भर की अदालतों में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही स्टेट लेवल लीगल सर्विसेज कम एंवायरमेंट कैंप में भाग लेंगे। यह कार्यक्रम शहर के कन्वेंशन हॉल में किया जाएगा। दुमका व्यवहार न्यायालय के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष कुमार शशि ने बताया कि मुख्य न्यायाधीश कन्वेंशन हॉल में राज्य के सभी जिलों में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत कार्यक्रम का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही स्टेट लेवल लीगल सर्विसेज कम एंवायरमेंट कैंप में भाग लेंगे। इस कार्यक्रम में लाभुकों के बीच परिस्पांचितियों का वितरण किया जाएगा।

महिला को दो करोड़ कमाई का झांसा देकर हत्या के तीन दोषियों को उम्रकैद

AGENCY DHANBAD :

जिले के बरवाअड्डा थाना क्षेत्र में वर्ष 2021 में सुनीता देवी की हुई सनसनीखेज हत्या मामले में अदालत ने शुक्रवार को दो लाख रुपये को दो करोड़ बनाने का लालच देकर की गई। इस हत्या के तीन दोषियों आनंद महतो, राजेश नाथीत और छोदू महतो को एडीजे-5 कुमार मनीष की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने तीनों को दोषियों पर 20 हजार रुपये जुमाना भी लगाया है। अदालत ने तीनों को दोषी करार देते हुए कहा कि यह हत्या योजनाबद्ध और विश्वासघात से जुड़ा जघन्य अपराध है। इस मामले में मृतका का पति कृष्ण कुमार भी साजिश में शामिल बताया गया है, लेकिन वह अब तक फरार चल रहा है। स्टेशन मास्टर पद पर कार्यरत कृष्ण कुमार की तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। यह घटना 29 जून 2021 की है, जब कृष्ण कुमार अपनी पत्नी सुनीता देवी और बेटी को लेकर कुमीर्डीह स्थित मां तारा रेस्टोरेंट पहुंचा था। आरोप है कि सुनीता को दो लाख को दो करोड़ बनाने का झांसा देकर रेस्टोरेंट बुलाया गया था। रेस्टोरेंट पहुंचने के कुछ ही देर बाद तीनों ने उसकी हत्या कर दी और सबूत मिटाने के लिए शव को सेप्टिक टैंक में फेंक दिया था। मामले का खुलासा तब हुआ जब सुनीता की बेटी रेस्टोरेंट पहुंची और वहां पड़े चप्पल और दुपट्टा को पहचान लिया। पुलिस ने तत्काल सेप्टिक टैंक की तलाशी ली, जहां से सुनीता का शव बरामद हुआ। अदालत के फैसले के बाद मृतका के परिजनों ने कहा कि उन्हें देर से सही, लेकिन न्याय मिला है।



पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। यह घटना 29 जून 2021 की है, जब कृष्ण कुमार अपनी पत्नी सुनीता देवी और बेटी को लेकर कुमीर्डीह स्थित मां तारा रेस्टोरेंट पहुंचा था। आरोप है कि सुनीता को दो लाख को दो करोड़ बनाने का झांसा देकर रेस्टोरेंट बुलाया गया था। रेस्टोरेंट पहुंचने के कुछ ही देर बाद तीनों ने उसकी हत्या कर दी और सबूत मिटाने के लिए शव को सेप्टिक टैंक में फेंक दिया था। मामले का खुलासा तब हुआ जब सुनीता की बेटी रेस्टोरेंट पहुंची और वहां पड़े चप्पल और दुपट्टा को पहचान लिया। पुलिस ने तत्काल सेप्टिक टैंक की तलाशी ली, जहां से सुनीता का शव बरामद हुआ। अदालत के फैसले के बाद मृतका के परिजनों ने कहा कि उन्हें देर से सही, लेकिन न्याय मिला है।

रामगढ़ : टुकड़ों में बरामद शव कहीं लापता सोनू का तो नहीं!

पहचान के लिए फोरेंसिक जांच कराएगी पुलिस, 17 सितंबर से गायब है युवक

AGENCY RAMGARH :

पुलिस ने रामगढ़ शहर के शिवू कॉलोनी नेहरू रोड से तीन महीने से लापता युवक का शव टुकड़ों में बरामद किया है। गुरुवार की देर रात पुलिस ने शव के टुकड़े हत्यारे के घर के समीप से ही बरामद किया। पुलिस ने एक हत्यारे को गिरफ्तार भी किया है। इस मामले की पुष्टि करते हुए रामगढ़ थाना प्रभारी नवीन प्रकाश पांडे ने बताया कि फिलहाल यह शव तीन महीने से लापता सोनू कुमार राम की प्रतीत हो रही है। आधिकारिक पुष्टि फोरेंसिक जांच के बाद ही होगी। आंदोलन भी किया था लोगों ने : रामगढ़ छावनी परिषद के स्टाफ क्वार्टर में रहने वाला सोनू कुमार राम, पिता विजय राम विश्वकर्मा



घटनास्थल पर मिले साक्ष्यों को एकत्र करती पुलिस व बरामद चापड़ तथा अन्य वस्तुएं



● फोटोन न्यूज

पूजा के दिन 17 सितंबर से लापता था। इस मामले में विजय राम के जरिए रामगढ़ थाने में गुमशुदगी की सूचना दर्ज कराई गई थी। अपने बेटे को वापस लाने के लिए लोगों ने आंदोलन भी किया था। लेकिन सोनू का कोई पता नहीं चला था।

अवैध संबंध हो सकता है हत्या का कारण
सोनू कुमार राम की हत्या के पीछे का कारण अवैध संबंध हो सकता है। पुलिस हत्यारे से इस मामले में पूछताछ कर रही है। पुलिस को कुछ संकेत भी मिले हैं। हत्यारे के परिवार वालों से भी पूछताछ हो रही है।

रंजीत सिंह के घर के पास ही मिला लास्ट लोकेशन
नेहरू रोड शिवू कॉलोनी के रहने वाले रंजीत सिंह उर्फ नाना भाई के घर के पास ही सोनू के मोबाइल का लास्ट लोकेशन पुलिस को मिला था। पिछले कई महीनों से पुलिस उसे तलाश रही थी। सोनू का कोई पता नहीं चला, तो घर वालों और मोहल्ले वालों पर पुलिस ने नजर दौड़ाई। इस दौरान जब रंजीत सिंह उर्फ नाना भाई से पूछताछ हुई तो वह टूट गया। उसने खुद पुलिस को वह जगह दिखाई जहां सोनू की हत्या की गई थी। साथ ही उसकी लाश के टुकड़े कर अलग-अलग टिकानों पर फेंका गया था।



सोनू राम को सिर के पीछे मारी गई थी गोली

RAMGARH : रामगढ़ छावनी परिषद स्टाफ क्वार्टर का रहने वाला सोनू कुमार राम हत्याकांड में लगातार नया खुलासा हो रहा है। शुक्रवार की शाम को सोनू की खोपड़ी धंधार पोखर के समीप जलकुभी के बीच में फेंकी हुई मिली। पुलिस ने जब खोपड़ी को देखा तो उसके सिर पर पीछे से गोली मारे जाने का निशान था। उसे घुटनों के बल बिठाकर गोली सिर के ठीक पीछे मारी गई। ताकि उसके बचने का कोई चांस ही ना रहे। हत्या के बाद शव को टिकाने लगाने के लिए उसे कई छोट-छोटे टुकड़ों में काट दिया गया था। सोनू के हाथ एक कुर्से से मिले। इसके अलावा अलग-अलग जगह से पूरे शरीर के अंग के कंकाल मिले हैं।

कंकाल देख स्पष्ट हुआ महीनों पहले हुई थी सोनू की हत्या
शिवू कॉलोनी, नेहरू रोड के धंधार पोखर के पास दलदल में फेंकी गई सोनू कुमार राम की खोपड़ी यह स्पष्ट करता है कि सोनू की हत्या महीनों पहले कर दी गई थी।

डीडीएमए की बैठक में डूबने व सड़क हादसों से हुई पांच मौतों की समीक्षा

मृतकों के आश्रितों को मिलेगा मुआवजा, लोगों को जोखिम वाली जगहों के प्रति किया जाएगा आगाह

AGENCY KHUNTI :

खूंटी समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में शुक्रवार को उपयुक्त आर. रॉनिटा की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार (डीडीएमए) की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें उन मामलों पर विस्तार से चर्चा की गई, जिनमें अन्य जिलों के लोगों की मौत खूंटी जिले में पानी में डूबने अथवा सड़क दुर्घटना में हुई थी। बैठक में कुल पांच मामलों की समीक्षा की गई, जिनमें रीमिक्स जलप्रपात में डूबने से दो लोगों की मौत, सोमार बाजार के पास स्थित कुएं में डूबने से एक व्यक्ति की मौत, पांडुपुडिंग जलप्रपात में डूबने से एक व्यक्ति की मौत और कुलडा पुल के पास सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की



आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक करती उपायुक्त

मौत का मामला शामिल रहा। ये सभी मृतक रांची, पश्चिम सिंहभूम और सिमडेगा जिलों के निवासी थे। समिति ने सभी मामलों में मृतकों के आश्रितों को मुआवजा देने की स्वीकृति प्रदान की। सरकारी प्रावधानों के अनुसार, पानी में डूबने से हुई मौत पर चार लाख रुपये, जबकि सड़क दुर्घटना में हुई मौत पर एक लाख रुपये मृतकों के

आश्रितों को दिए जाएंगे। बैठक के दौरान उपायुक्त ने अपर समाहता के माध्यम से सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने अंचलों में डीडीएमए की बैठक नियमित रूप से आयोजित करें। उन्होंने कहा कि जलप्रपातों में बढ़ते जलस्तर के कारण लोगों को सचेत करने और जोखिम वाले क्षेत्रों में जाने से रोकने के लिए व्यापक

जागरूकता अभियान चलाया जाए। नए साल पर संभावित भीड़ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अधिक जलस्तर वाले स्थानों पर अनिवार्य बैरिकेडिंग सुनिश्चित करने का आदेश भी दिया, ताकि किसी भी तरह की अग्रिय घटना को टाला जा सके। बढ़ती ठंड को देखते हुए भी उपायुक्त ने नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी एवं संबंधित अधिकारियों को चौक-चौराहों पर अलाव की समुचित व्यवस्था करने का निर्देश दिया। बैठक में पुलिस अधीक्षक मनीष टोपों, उप विकास आयुक्त अलोक कुमार, अपर समाहता परमेश्वर मुंडा, सिविल सर्जन डॉ. एन. मांडी, नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

गिरिडीह : बीस वर्षों से फरार नक्सली किया गया गिरफ्तार

GIRIDIH : अर्धसैनिक बलों के सहयोग से बिहार एसटीएफ ने गिरिडीह की कैदी वाहन घटना में शामिल इनामी भाकपा माओवादी मोतीलाल किस्कू को संयुक्त अभियान में गिरफ्तार किया है। करीब 20 वर्षों से फरार इनामी नक्सली मोती लाल किस्कू को गिरिडीह के देवरी थाना इलाके से पकड़ा गया है। मिली जानकारी के अनुसार गुप्त सूचना पर फरार नक्सली मोती लाल को देवरी के गांव से गुरुवार रात में उस वक्त दबोचा गया जब वह अपने गांव में आराम फरमा रहा था। इसी दौरान जाँट ऑपरेशन में चकाई पुलिस और जवानों ने मोती लाल को दबोचा। जानकारी के अनुसार मोती लाल जमुई जिले के चकाई के चिहरा थाना इलाके के हरनी गांव का रहने वाला था, और पिछले 20 वर्षों से नक्सली संगठन



में सक्रिय था। मोती लाल चकाई के जीवलाल पासवान हत्याकांड में शामिल था, इसके अलावा इसके खिलाफ जमुई और गिरिडीह के कई थानों में नक्सली घटना के केस दर्ज हैं। मोतीलाल मुठभेड़ में मारे गये जौनल कमेटी के सदस्य और इनामी नक्सली चिराग दा के दरते में भी शामिल था। और इसके दरते में एके 47 लेकर चलता था। गिरिडीह में 16 साल पहले हुए कैदी वाहन कांड में भी इसका नाम सामने आ रहा है।

केंदुआडीह गैस रिसाव मामले में कोयला मंत्री से मिले सांसद

AGENCY PALAMU :

जिले के चैनपुर प्रखंड की मझिगांवा की पंचायत समिति सदस्य प्रभा देवी शुक्रवार को निर्विरोध प्रमुख पद के लिए चुनी गयीं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच निवाची पदाधिकारी सह सदर एसडीओ सुलोचना मीणा, प्रशिक्षु आईएएस हिमांशु लाल की देखरेख में प्रखंड कार्यालय स्थित सभागार में चुनाव संपन्न हुआ। उल्लेखनीय है कि चैनपुर में करीब पांच माह पहले प्रखंड प्रमुख के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के बाद से ही पंसस के प्रमुख पद पर चुनाव कराने की तैयारी चल रही थी। वहीं सुबह 10 बजे चुनाव प्रक्रिया शुरू की गयी। चुनाव में कुल 31 में 30 पंचायत समिति सदस्यों ने हिस्सा लिया। प्रमुख पद के लिए मात्र प्रभा देवी



DHANBAD : धनबाद के केंदुआडीह में 10 दिन से हो रहे गैस रिसाव मामले में गिरिडीह के सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी शुक्रवार को केन्द्रीय कोयला व खान मंत्री जी. किशन रेड्डी से मिले। नई दिल्ली स्थित शास्त्री भवन में मुलाकात के दौरान सांसद ने गैस रिसाव को घटना के अलावा कोल माईंस से जुड़े विभिन्न ज्वलंत विषयों, उसके समाधान, खनिज रॉयल्टी, कोल माईंस के लिए जमीन अधिग्रहण, रैयनों को मुआवजा व नियोजन, विस्थापितों के पुनर्वास, डीएमएफटी- सीएसआर फंड के इस्तेमाल और कोल परियोजनाओं को सुचारू करने में आ रही बाधाओं से अवगत कराया। सांसद ने केन्द्रीय मंत्री को बताया कि कोयला व खान क्षेत्र के लिए दूसरे राज्यों में पूर्णकालिक अर्थारिटी या ट्रिब्यूनल है, लेकिन झारखंड में नहीं है। सांसद ने बताया कि केन्द्रीय मंत्री ने आवश्यक किया है कि जल्द ही इस पर प्रभावी कार्रवाई कर पूर्णकालिक ट्रिब्यूनल का गठन किया जाए।



कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी के साथ सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी

सेप्टिक टैंक में फेंक दिया था। मामले का खुलासा तब हुआ जब सुनीता की बेटी रेस्टोरेंट पहुंची और वहां पड़े चप्पल और दुपट्टा को पहचान लिया। पुलिस ने तत्काल सेप्टिक टैंक की तलाशी ली, जहां से सुनीता का शव बरामद हुआ। अदालत के फैसले के बाद मृतका के परिजनों ने कहा कि उन्हें देर से सही, लेकिन न्याय मिला है।

पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। यह घटना 29 जून 2021 की है, जब कृष्ण कुमार अपनी पत्नी सुनीता देवी और बेटी को लेकर कुमीर्डीह स्थित मां तारा रेस्टोरेंट पहुंचा था। आरोप है कि सुनीता को दो लाख को दो करोड़ बनाने का झांसा देकर रेस्टोरेंट बुलाया गया था। रेस्टोरेंट पहुंचने के कुछ ही देर बाद तीनों ने उसकी हत्या कर दी और सबूत मिटाने के लिए शव को सेप्टिक टैंक में फेंक दिया था। मामले का खुलासा तब हुआ जब सुनीता की बेटी रेस्टोरेंट पहुंची और वहां पड़े चप्पल और दुपट्टा को पहचान लिया। पुलिस ने तत्काल सेप्टिक टैंक की तलाशी ली, जहां से सुनीता का शव बरामद हुआ। अदालत के फैसले के बाद मृतका के परिजनों ने कहा कि उन्हें देर से सही, लेकिन न्याय मिला है।

चैनपुर की निर्विरोध प्रमुख बनीं प्रभा, पांच माह से खाली था पद

AGENCY PALAMU :

जिले के चैनपुर प्रखंड की मझिगांवा की पंचायत समिति सदस्य प्रभा देवी शुक्रवार को निर्विरोध प्रमुख पद के लिए चुनी गयीं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच निवाची पदाधिकारी सह सदर एसडीओ सुलोचना मीणा, प्रशिक्षु आईएएस हिमांशु लाल की देखरेख में प्रखंड कार्यालय स्थित सभागार में चुनाव संपन्न हुआ। उल्लेखनीय है कि चैनपुर में करीब पांच माह पहले प्रखंड प्रमुख के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के बाद से ही पंसस के प्रमुख पद पर चुनाव कराने की तैयारी चल रही थी। वहीं सुबह 10 बजे चुनाव प्रक्रिया शुरू की गयी। चुनाव में कुल 31 में 30 पंचायत समिति सदस्यों ने हिस्सा लिया। प्रमुख पद के लिए मात्र प्रभा देवी



प्रमुख चुने जाने के बाद सनर्थकों से धिरी प्रजा देवी

ने ही नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया, जिसे जांच के बाद सही पाया गया। इसके बाद विधिवत उनके निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा कर दी गई। निर्वाचन के बाद उन्हें प्रमाण पत्र देकर पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। जीत के बाद उनके समर्थकों ने उन्हें फूल माला पहनाकर और गुलाल लगाकर खुशी प्रकट की। योजनाओं को धरातल पर

उतारना प्राथमिकता : प्रमुख
मौके पर नव निर्वाचित प्रखंड प्रमुख प्रभा देवी ने जनकल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारना ही उनकी पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि पंचायत समिति सदस्यों से आपसी समन्वय स्थापित कर प्रखंड में विकास को गति प्रदान करना भी उनके मुख्य कार्यों में शामिल रहेगा।

खुलासा पुलिस की जांच में हुआ खुलासा, फैमिली कार की आड़ में हो रहा मादक पदार्थ का धंधा

शराब तस्करी में माफिया कर रहे युवतियों का इस्तेमाल

PHOTON NEWS PALAMU :

पलामू जिले में अब शराब की तस्करी के लिए माफिया लड़कियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। माफिया युवतियों को कम समय में अधिक पैसा कमाने का लालच देकर अवैध धंधे में शामिल कर रहे हैं। यही नहीं, माफिया अब शराब की तस्करी के लिए ट्रक-वैन की जगह फैमिली कार का उपयोग कर रहे हैं, जिससे पुलिस को शक नहीं हो। इस मामले का खुलासा तब हुआ, जब गत दिनों पलामू के पांकी थाना क्षेत्र के एनवा-मैनवा जंगल में पुलिस ने अवैध शराब की फैक्ट्री पर छापेमारी की थी। इसी दौरान जांच-पड़ताल में पुलिस को शराब तस्करी के नए तरीके का पता चला। जिस कार के माध्यम से पुलिस अवैध शराब की फैक्ट्री तक पहुंची थी, वह फैमिली कार की तरह इस्तेमाल की जा रही थी। शराब फैक्ट्री पर छापेमारी के दौरान



कार की जांच के दौरान पुलिस को बताते थे पति-पत्नी
माफिया शराब की खेप को जिस गाड़ी से पहुंचाते थे, उसमें एक युवक और एक युवती को बैठाया जाता था। रास्ते में वाहन चेकिंग के दौरान जब पुलिस कार की जांच के लिए रोकती थी, उसमें बैठे युवक-युवती अपने आप को कपल या पति-पत्नी बताते थे। पुलिस को यह सामान्य बात लगती थी और कार को बिना गहन जांच के जाने दिया जाता था। बताया जाता है कि माफिया कुछ हफ्तों से ऐसा कर रहे थे। ऐसे में पुलिस सिर्फ टुक या वैन की गहन जांच करती थी और उसमें शराब पकड़ी भी जा रहे थे।

युवती को बैठाते थे आगे : एसपी
जांच-पड़ताल के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि युवतियों का इस्तेमाल बड़ी योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा था। शराब माफिया जिस कार में शराब को खेप ले जाते थे, उसमें आगे की सीट पर युवती को बैठाया जाता था। पुलिस को इसके अलावा भी शराब के धंधे से जुड़ी कई नई बातों की जानकारी मिली है। शराब माफिया अब तस्करी के लिए कारों का उपयोग ज्यादा कर रहे हैं।

बिहार चुनाव के दौरान पकड़ी गई थी 70 करोड़ की शराब

पलामू पुलिस के अनुसार, बिहार से सटा होने की वजह से यहां से बड़ी मात्रा में शराब की तस्करी हो रही है। बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले पलामू जिले में 33 करोड़ रुपये के अवैध मादक पदार्थ जप्त किए गए थे, जिसमें सबसे ज्यादा शराब थी। वहीं विधानसभा और लोकसभा चुनाव के दौरान 70 करोड़ रुपये की शराब पकड़ी गई थी।

गाड़ियों का गॉडफिकेशन भी करते हैं तस्करी

शराब माफिया समय-समय पर तस्करी का तरीका बदलते रहते हैं। अक्सर बड़ी गाड़ियों में माफिया गॉडफिकेशन करके शराब छिपाते हैं। अब छोटी गाड़ियों का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। छोटी गाड़ियों में बदलाव किया जाता है। उसके अंदरूनी बनावट में बदलाव कर-के शराब की तस्करी की जाती है।

पुतले के साथ शतयात्रा निकाल रहे विस्थापित रोके गए

BOKARO : बोकारो डीसी के पुतले के साथ शतयात्रा निकाल रहे विस्थापित नौजवान संघर्ष मोर्चा के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोक दिया। बोकारो जिला प्रशासन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए यह शव यात्रा निकाली जा रही थी लेकिन जैसे ही विस्थापित बोकारो हवाई अड्डा के पास पहुंचकर शतयात्रा निकालने की तैयारी हो कर रहे थे कि वहां मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में पुलिस ने उन्हें रोक दिया। विस्थापित नेता अरुण कुमार महतो का आरोप है कि जिला प्रशासन भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। अधिकारी नियम के विरुद्ध पचां काट रहे हैं। सहायक कर्मचारी पुनर्वासित भूमि लूटने की कोशिश कर रहे हैं। विस्थापितों का कहना है कि अगर उपायुक्त भ्रष्टाचार के खिलाफ संज्ञान नहीं लेंगे तो फिर से शतयात्रा निकाली जाएगी। वहीं मजिस्ट्रेट सेवारत साहू ने कहा कि विस्थापितों द्वारा पुतला बनाकर लाया गया था, जिसे जब्त कर लिया गया है।

नर्स ने लगाई फांसी, पिता ने जताई हत्या की आशंका

RAMGARH :

शहर के साहू कॉलोनी स्थित राम लौलीन साव के मकान में रह रही एक नर्स लवली कुमारी ने शुक्रवार को फंदे से लटक कर खुदकुशी कर ली। घटना की सूचना पाकर रामगढ़ थाना प्रभारी नवीन प्रकाश पांडे घटना स्थल पहुंचे। उन्होंने सीढ़ी में फंदे से लटकती नर्स के शव को उतरवाया और पोस्टमॉर्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। साथ ही मृतका के परिजनों को इसकी जानकारी दी। जानकारी के अनुसार ओरमांडी थाना क्षेत्र के पिपरबंडा निवासी लवली कुमारी (23) शहर के चट्टी बाजार स्थित बरेलिया नर्सिंग होम में नर्स के रूप में कार्यरत थी। यहां वह फरवरी माह से रह रही थी उससे सप्ताह रह रही अन्ध नर्स ने बताया कि गुरुवार की रात हम सभी नर्सिंग होम से आकर खाना



खाकर सोने चले गए। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को देखा कि सीढ़ी में बंधे एक फंदे से लवली का शव लटक चुका हुआ है। अपनी बेटी की निधन की सूचना पाकर रामगढ़ पहुंचे लवली के पिता राजन मुंडा ने उसकी हत्या की आशंका जताई है। इधर, पुलिस ने नर्स का मोबाइल जब्त कर छानबीन में जुट गई है।

संगठित आपराधिक गिरोहों की ताकत ध्वस्त करने के लिए पुलिस ने कसी कमर

PHOTON NEWS RANCHI : झारखंड के विभिन्न जिलों में सक्रिय संगठित आपराधिक गिरोहों की ताकत को ध्वस्त करने के लिए पुलिस ने कमर कस ली है। कई गैंग्स के पाकिस्तानी तस्करों के साथ चल रहे अवैध हथियार कनेक्शन की जांच तेज कर दी गई है। अब तक की जांच में झारखंड के तीन बड़े संगठित आपराधिक गिरोहों के पाकिस्तान के तस्करों से सीधे संबंध सामने आ चुके हैं। झारखंड पुलिस इस अंतरराष्ट्रीय हथियार तस्कारी नेटवर्क को पूरी तरह खत्म करने की रणनीति पर काम कर रही है। झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर्स को पाकिस्तान से हथियार कौन-कौन सप्लाई कर रहा है, तस्कारी का रूट क्या है और इसमें कितने सफेदपोश लोग शामिल हैं, इसकी गहन जांच झारखंड पुलिस कर रही है। जांच में सामने आया है कि झारखंड के बड़े आपराधिक गुट सीधे पाकिस्तान से हथियार मंगा रहे हैं और उनका इस्तेमाल राज्य में आतंक मचाने के लिए कर रहे हैं।

पाकिस्तान के तस्करों से सीधे संबंध के मामले की तेजी से की जा रही जांच, पंजाब के रास्ते हथियारों को मंगा कर झारखंड में किया जा रहा इस्तेमाल इस नेटवर्क से जुड़े आधा दर्जन से अधिक अपराधियों को किया जा चुका है गिरफ्तार, टेरेर फंडिंग के जरिए भी पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं कई कुख्यात

अजरबैजान से गिरफ्तार मयंक सिंह, अमन साहू (मृत) के बाद अब कुख्यात प्रिंस खान और गैंगस्टर सुजीत सिन्हा के तार भी पाकिस्तान से जुड़े इसी तरह दुबई में बैठकर अपने गैंग का संचालन कर रहा प्रिंस खान भी पाक से मंगवा रहा हथियार पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती- अपराधियों तक कैसे पहुंच रहा हथियारों का जखीरा



विदेश में बैठकर गैंग चला रहा राहुल सिंह

अब तक की जांच में यह तथ्य सामने आ चुका है कि पाकिस्तान से पंजाब के रास्ते हथियार झारखंड पहुंच रहे हैं। इस नेटवर्क से जुड़े झारखंड के आधा दर्जन से अधिक अपराधियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं पंजाब पुलिस भी इस हथियार नेटवर्क के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। बताया जाता है कि टेरेर फंडिंग के जरिए भी झारखंड के कई कुख्यात अपराधी पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। अजरबैजान से गिरफ्तार मयंक सिंह, अमन साहू (मृत) के बाद अब कुख्यात प्रिंस खान और गैंगस्टर सुजीत सिन्हा के तार भी पाकिस्तान से जुड़े पाए गए हैं। मामले में झारखंड पुलिस ने टेरेर फंडिंग के एंगल से भी जांच शुरू कर दी है। अमन साहू के मारे जाने के बाद राहुल सिंह विदेश में बैठकर गैंग चला रहा है। उसके गिरोह के पास भी भारी मात्रा में हथियार हैं, जिनमें से अधिकांश पाकिस्तान से मंगवाए गए हैं। इसी तरह दुबई में बैठकर अपने गैंग का संचालन कर रहा प्रिंस खान भी पाकिस्तान से हथियार मंगा रहा है।

रांची पुलिस की जांच में हो चुका है खुलासा

सुजीत सिन्हा गिरोह का भी पाकिस्तानी हथियार तस्करों से सीधा कनेक्शन सामने आया है। प्रिंस खान और सुजीत सिन्हा समेत उनके गुर्गों का पाकिस्तानी तस्करों से प्रत्यक्ष संबंध है। दोनों गैंगस्टर हवाला के जरिए पाकिस्तान व दुबई में पैसा भेजकर हथियार खरीदते हैं और पंजाब के रास्ते झारखंड मंगवाते हैं। यह खुलासा रांची पुलिस की जांच में हो चुका है। झारखंड पुलिस के प्रवक्ता-सह-आईजी (अभियान) ने बताया कि इस हथियार नेटवर्क की जड़ तक पहुंचने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। जांच तेज गति से चल रही है, इसलिए इसकी प्रगति से जुड़ी विस्तृत जानकारी अभी मीडिया के सामने नहीं लाई जा सकती। इतना जरूर है कि हथियार नेटवर्क को तोड़ने और विदेश भागे अपराधियों के खिलाफ भी कार्रवाई जारी है।

स्पेशल टीम भी लगातार कर रही काम

सुजीत सिन्हा की पत्नी रिया सिन्हा सहित आधा दर्जन अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद यह बड़ा सच सामने आया था। रिया सिन्हा व अन्य गिरफ्तार अपराधियों पर टेरेर फंडिंग के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। झारखंड पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि अत्याधुनिक विदेशी हथियारों का जखीरा राज्य के अपराधियों तक कैसे पहुंच रहा है। इस पर रोक लमाना अत्यंत जरूरी है। इसी वजह से झारखंड पुलिस के साथ-साथ एक स्पेशल टीम भी इस मामले में काम कर रही है। कल तक जो अपराधी बिहार के मुंगेर और मध्या प्रदेश के कुछ अवैध कारखानों से देशी हथियार खरीदते थे, आज वे ऑस्ट्रेलिया और अन्य विदेशी पिस्टल व राइफल का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह झारखंड पुलिस के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गया है।

11 विदेशी हथियार अब तक बरामद नहीं

पुलिस जांच में सामने आया है कि गैंगस्टर सुजीत सिन्हा और उसके गुर्गों ने पाकिस्तान से कुल 21 विदेशी हथियार झारखंड मंगवाए थे। इनमें से 10 हथियार पुलिस बरामद कर चुकी हैं, लेकिन शेष 11 अत्याधुनिक हथियार अभी तक बरामद नहीं हो सके हैं। पुलिस की टीमें इन्हें बरामद करने के लिए लगातार छापेमारी कर रही हैं। गैंगस्टर सुजीत सिन्हा पंजाब के गैंग से विदेशी हथियार झारखंड लाने के लिए लड़कियों का इस्तेमाल करता था। पुलिस के अनुसार, सुजीत का करीबी रिश्ता आनंद उर्फ सिंघा को हथियार लाने-लेजाने की जिम्मेदारी दी गई थी।

BRIEF NEWS

अनिल शर्मा की रिहाई की मांग की याचिका खारिज

RANCHI : रांची के कुख्यात अपराधी अनिल शर्मा को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने अनिल शर्मा की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें समय पूर्व रिहाई का आग्रह किया गया था। अनिल शर्मा रांची जेल में कैदी भोमा सिंह की हत्या से जुड़े मामले में सजा काट रहे हैं। इस मामले में अनिल शर्मा को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। यह 28 साल से जेल में हैं और उसने अपनी रिहाई के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। यह मामला 22 जनवरी 1999 का है, जब अनिल शर्मा ने रांची के बिरसा मुंडा जेल में बंद रहते हुए अन्य अपराधियों के साथ मिलकर कैदी भोमा सिंह की हत्या कर दी थी।

प्रशिक्षण देने के लिए 9 अधिकारी प्रतिनियुक्त

RANCHI : झारखंड पुलिस के आईजी प्रशिक्षण के अनुरोध पर श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान रांची में आयोजित होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए एक आईपीएस सहित कुल नौ पुलिस अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया गया है। यह प्रशिक्षण जेपीएससी 2023 के माध्यम से चयनित कुल 342 पदाधिकारियों के लिए आयोजित किया जा रहा है। प्रशिक्षण कार्यक्रम 16 दिसंबर से शुरू होगा, जो 28 दिसंबर तक चलेगा। सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को 15 दिसंबर तक श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान में अपना योगदान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।

जगह-जगह सड़कों पर लगा रहे जाम, पैसेंजर के लिए करते हैं मारामारी राजधानी में ऑटो-ई-रिक्शा वालों ने किया नाक में दम, हुए बेलगाम

PHOTON NEWS RANCHI : राजधानी रांची में ऑटो और ई-रिक्शा चालकों की मनमानी ने शहरवासियों की परेशानी बढ़ा दी है। स्थिति यह है कि सड़कों पर जगह-जगह जाम लग रहा है और पैसेंजर बैठाने के लिए चालकों की मारामारी आम बात हो गई है। ट्रैफिक नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ट्रैफिक पुलिस के लिए भी ये लोग फिलहाल सिरदर्द बने हुए हैं। हालांकि ट्रैफिक पुलिस की ओर से इनके खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। यहीं वजह है कि दिनों दिन इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। रांची में इस समय 24,746 ऑटो और करीब 23,217 ई-रिक्शा सड़कों पर दौड़ रहे हैं। जबकि शहर में केवल द्वाइ हजार ऑटो को ही आधिकारिक परमिट मिला है। बाकी ऑटो बिना अनुमति के चल रहे हैं, जिससे न सिर्फ राजधानी की सड़कों पर दबाव बढ़ा है, बल्कि अवैध संचालन के कारण ट्रैफिक पुलिस के

ट्रैफिक नियमों की खुलेआम उड़ाई जा रही धज्जियां, नहीं होती करवाई



द्वाइ हजार ऑटो को ही रांची में चलने की मिली है परमिट

हर दिन इनकी वजह से लोग समस्याओं को झेल रहे हैं। स्कूल जाने वाले बच्चों, ऑफिस जाने वाले लोगों और मार्केट आने-जाने वालों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है। कई बार ऑटो चालक किराए को लेकर भी मनमानी करते हैं और तय रेट से अधिक पैसा मांगते हैं। लोगों का कहना है कि यदि ऑटो-रिक्शा और ई-रिक्शा चालकों पर सख्ती नहीं की गई तो आने वाले दिनों में स्थिति भयावह हो सकती है। प्रशासन ने पहले भी कई बार अभियान चलाकर चालकों को नियमों का पालन करने की चेतावनी दी, लेकिन कुछ दिनों बाद स्थिति फिर जस की तस हो गई है। परिवहन विभाग ने ये आदेश दिया था कि राजधानी में केवल परमिट वाले ऑटो का परिचालन

रूटवार्ड की योजना ठंडे बस्ते में

मेन रोड, अल्ट्रा एका चौक, कांटाटोली, लालपुर, किशोरगंज, हरमू जैसे क्षेत्रों में यह समस्या सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। रांची नगर निगम ने शुरूआत में ई-रिक्शा के लिए रूट निर्धारित किया था। वहीं दूसरे रूट पर परिचालन करने पर दो बार फाइन लगाए और फिर जबी का नियम लागू किया गया था। लेकिन, कुछ दिनों में ही ये योजना ठंडे बस्ते में चली गई। आज ये ई-रिक्शा वाले बिना नियम कानून के परिचालन किसी भी सड़क में कर रहे हैं। न तो उन्हें कोई रोकने वाला है न कोई टोकने वाला। अब तो ई-रिक्शा वालों ने राजधानी के मेन रोड को भी अव्यवस्थित कर दिया है, जबकि कुछ समय पहले इन रोड में ई-रिक्शा की एंट्री पर रोक लगा दी गई थी। अब ये फिर से जाम का कारण बन रहे हैं।

NEWS BOX

जैक परीक्षा के लिए केंद्रों के चयन को लेकर बैठक, डीसी बोले- नकल की न हो गुंजाइश

RANCHI : जैक वॉशिक माध्यमिक और इंटरमीडिएट परीक्षा-2026 के लिए परीक्षा केंद्रों और मूल्यांकन केंद्रों के चयन को लेकर शुक्रवार को समाह्वणालय में जिला चयन समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त मंजुनाथ भजन्त्री ने की। उपयुक्त ने बैठक में स्पष्ट निर्देश दिया कि परीक्षा केंद्रों का चयन पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी होना चाहिए। जिससे कि किसी भी तरह की नकल या अनियमितता की कोई गुंजाइश न रहे। उन्होंने कहा कि ऐसे स्कूलों का चयन किया जाए जहां पर्याप्त संख्या में कक्ष उपलब्ध हों, सीसीटीवी कैमरे लगे हों, पर्याप्त लाइट की व्यवस्था, पेयजल और शौचालय की सुविधा मौजूद हो। साथ ही उन्होंने सभी केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि परीक्षार्थियों को केंद्र तक पहुंचने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो, इसके लिए सुगम यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने की जरूरत है। बैठक में विभिन्न प्रस्तावित केंद्रों की सूची पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया और परीक्षार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कुछ केंद्रों में बदलाव करने का निर्णय लिया गया। अधिकारियों ने सर्वसम्मति से कहा कि परीक्षा-2026 को पूरी तरह शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उप विभागाध्यक्ष सौरभ कुमार भुवनिग्या, पुलिस अधीक्षक नगर पारस राणा, विकास शिक्षा पदाधिकारी विनय कुमार सहित सांसद और विधायक प्रतिनिधि के अलावा अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे।

रांची के लिकर बार एंड रेस्टोरेंट का लाइसेंस रद्द एसाएसपी की रिपोर्ट पर डीसी ने की कार्रवाई

RANCHI : राजधानी रांची के अरगोड़ा चौक स्थित लिकर बार एंड रेस्टोरेंट का लाइसेंस डीसी मंजुनाथ भजन्त्री ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई एसाएसपी की रिपोर्ट के आधार पर की गई है। कई तरह के विवादों में नाम आने के बाद रांची के अरगोड़ा चौक स्थित लिकर बार एंड रेस्टोरेंट का लाइसेंस रांची डीसी ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। आदेश पत्र में बताया गया है कि यह कार्रवाई वरीय पुलिस अधीक्षक की अनुसंधान पर उत्पन्न अधिनियम की धारा 42 के तहत की गई है। एसाएसपी की रिपोर्ट में कहा गया है कि अरगोड़ा चौक का रास्ता बेहद व्यस्त है और वीथीआवृत्ती आवामगम का प्रमुख मार्ग है। ऐसे में बार के कारण अवसर होने वाले झगड़े से कानून-व्यवस्था पर गंभीर खतरा बना रहता है। रिपोर्ट के अनुसार बार संचालक की ओर से ट्रॉसजैडर (टीजे) बुलाकर ड्रांस एवं ड्रांस वलब का आयोजन बार-बार किया जाता था। इस दौरान ग्राहकों के बीच कई बार मारपीट और हंगामा हो चुका है। प्रशासन ने माना है कि बार में लगातार हो रहे झगड़े और सड़क पर उत्पन्न विवाद से किसी भी समय बड़ी आप्रिय घटना हो सकती है।

कॉमर्स कॉन्सेप्ट संस्थान में मना वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे

RANCHI : पिस्का मोड़ स्थित कॉमर्स कॉन्सेप्ट संस्थान में वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे के मौके पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। मानव अधिकार एसोसिएशन रांची जिला के अध्यक्ष विवेक कुमार, संस्था के अन्य सदस्यों और निदेशक सोनू कुजूर ने बच्चों को मानव अधिकारों व ट्रैफिक नियमों की विस्तृत जानकारी दी। बच्चों ने बच्चों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने, कानून का सम्मान करने और सड़क सुरक्षा का पालन करने की सलाह दी। कार्यक्रम में छात्रों को उज्ज्वल भविष्य के लिए मार्गदर्शन भी प्रदान किया गया।

एसआईआर प्रक्रिया में बड़ी संख्या में मतदाताओं के काटे जा रहे नाम : कैलाश यादव

RANCHI : प्रदेश राजद प्रवक्ता कैलाश यादव ने आरोप लगाया कि देशभर में चल रही एसआईआर प्रक्रिया के पीछे केंद्र सरकार का छिपा हुआ एनआरसी एजेंडा काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग जैसी स्वतंत्र संस्था से अपेक्षा होती है कि वह निष्पक्ष काम करे। लेकिन वर्तमान में वॉटर चोर-गद्दी छोड़ रैली देश में लोकतंत्र बचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि देश के लोकतांत्रिक ढांचे पर मंडरा रहे खतरों और चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों से जनता को अलग कराना इस रैली का मुख्य उद्देश्य है। राकेश सिन्हा ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार की तंत्र का दुरुपयोग कर रही है और निर्वाचन आयोग की भूमिका पर उठ रहे सवाल को अनदेखा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लग रहे हैं। लेकिन भाजपा पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराना नहीं चाहती। उन्होंने कहा कि रैली के माध्यम से जनता के बीच यह संदेश जाणूना कि किस प्रकार भाजपा लोकतांत्रिक मूल्यों को क्षति पहुंच रही है और चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित कर रही है। उन्होंने दावा किया कि यह रैली ऐतिहासिक शाब्दित होगी और देशभर में एक मजबूत संदेश प्रसारित करेगी कि वर्तमान शासन लोकतांत्रिक परंपराओं को कमजोर कर रहा है। उन्होंने आगे बताया कि रैली में भाग लेने के लिए झारखंड से बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं।

उप-निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ ऑनलाइन समीक्षा बैठक वेबसाइट पर विगत गहन पुनरीक्षण की सूची सर्वेबल फॉर्मेट में उपलब्ध : सीईओ

PHOTON NEWS RANCHI : शुक्रवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (सीईओ) के. रवि कुमार ने सभी जिलों के उप-निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ ऑनलाइन समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने कहा कि जिन मतदाताओं का नाम विगत गहन पुनरीक्षण के दौरान झारखंड की मतदाता सूची में नहीं था और वे पहले किसी अन्य राज्य की सूची में दर्ज थे, वे संबंधित राज्य की पिछली मतदाता सूची से अपना नाम खिंच सकते हैं। इसके बाद वे अपने बीएलओ से संपर्क कर आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग

और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की आधिकारिक वेबसाइट पर विगत गहन पुनरीक्षण की मतदाता सूची सर्वेबल फॉर्मेट में उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि मतदाता अपने अथवा अपने परिजनों के नाम खोजने के लिए 1950 पर कल कर सहायता प्राप्त कर सकते हैं। राज्य में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण की तैयारियों के तहत बीएलओ ऐप में पुराने और वर्तमान मतदाता सूची की मैपिंग की जा रही है। अन्य राज्यों से आए मतदाताओं की मैपिंग मैनुअल रजिस्टर के माध्यम से की जाए, ताकि पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान किसी को परेशानी न हो।

अचानक बैग झपटकर फरार हो गए थे अपराधी बिहार में कोढ़ा गैंग के ठिकाने पर रांची पुलिस की छापेमारी, छिन्तई के जेवरात बरामद

PHOTON NEWS RANCHI : रांची पुलिस ने डीपीवो बरियारतू के पास बैंक ऑफ इंडिया के सामने हुई एक बड़ी छिन्तई की घटना का खुलासा किया। एसएसपी राकेश रंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर रांची पुलिस की टीम ने बिहार के कटिहार जिले में कोढ़ा गैंग के ठिकाने पर छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने रांची में छिन्तई के 60 लाख रुपये के जेवरात बरामद किए हैं। शुक्रवार को रांची पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए बताया कि बरियारतू में अपराधियों ने एक दम्पति से लगभग 55 से 60 लाख

रुपये मूल्य के सोने और चांदी के जेवरात से भरा बैग छीन लिया था। मामले की अनुसंधान के आधार पर बिहार के कटिहार से कोढ़ा गैंग की सलिपता पाई और चोरी गए समस्त जेवरात को बरामद कर लिया है। आठ दिनों के जयप्रकाश नगर, बूटी मोड़ निवासी निलय प्रकाश अपनी पत्नी के साथ डीपीवो बरियारतू के पास स्थित बैंक ऑफ इंडिया शाखा गए थे। बैंक लॉकर से जेवरात निकालकर जब वे अपने चारपहिया वाहन से घर पहुंचे, तो उनकी पत्नी जेवरों से भरा बैग कंधे पर लटकाए घर का मोटर खोलने लगी। इसी दौरान एक मोटर साइकिल पर सवार दो अज्ञात व्यक्तियों ने अचानक उनकी पत्नी के कंधे से बैग झपट लिया और फरार हो गए।

बेहतर भविष्य आवासीय स्तर पर कई प्रकार की ट्रेनिंग देकर बेरोजगारों को बनाया जाता है सक्षम गरीबों के लिए रोजगार की उम्मीद बनकर उमरे कौशल कॉलेज

PHOTON NEWS RANCHI : युवाओं के लिए रोजगार की जरूरत ज़िंदगी में सबसे बड़ी है। इसे ध्यान में रखते हुए हेमंत सरकार ने गरीब युवाओं को स्वीकृति मिली कर रोजगार देने की विशेष व्यवस्था की है। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित कौशल कॉलेज इस काम को करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इन कौशल कॉलेजों को राज्य सरकार के कल्याण विभाग के तहत संचालित होता है और प्रैक्टिस/आईटी एलुमनी रीच फॉर इंडिया फाउंडेशन द्वारा प्रबंधित किया जाता है। प्रेक्षा फाउंडेशन की निगरानी में संचालित ये कॉलेज झारखंड में तकनीकी शिक्षा और रोजगार का सबसे प्रभावी मॉडल बनकर उभरे हैं। राज्य के 24 जिलों में कौशल कॉलेज क्रियाशील हैं, जबकि 30 कॉलेजों को स्वीकृति मिली है। इन कॉलेजों में आईटी, हार्स्पेटेलिटी, रिटेल, सिक्वोरिटी, कंस्ट्रक्शन, मार्केटिंग, हेल्थ, टेक्सटाइल और इलेक्ट्रिकल जैसे लगभग 35 से अधिक ट्रेड संचालित किए जाते हैं। इन सभी कार्यक्रमों को नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) से प्रमाणित किया गया है, जिससे छात्रों को देश और विदेश की उद्योगों में मान्यता मिलती है।

हेल्थ, टेक्सटाइल व इलेक्ट्रिकल सहित करीब 35 से अधिक ट्रेड किए जा रहे संचालित नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क से पाठ्यक्रमों को किया गया है प्रमाणित

राज्य के सभी जिलों में इस प्रकार के 30 कॉलेजों को दी गई है मान्यता

70 प्रतिशत प्रशिक्षण प्रैक्टिकल और उद्योग आधारित

कौशल कॉलेज में केवल सैद्धांतिक पढ़ाई नहीं कराई जाती, बल्कि 70 प्रतिशत प्रशिक्षण प्रैक्टिकल और उद्योग आधारित होता है। कॉलेज की संरचना को इस तरह विकसित किया गया है कि छात्र वास्तविक कार्यस्थल जैसा अनुभव प्राप्त कर सकें। इन कॉलेजों में आधुनिक लैब और किचन स्टूडियो, इंडस्ट्रियल ग्रेड मशीनें, स्मार्ट क्लासरूम, वर्कशॉप और प्रैक्टिकल हॉल, हॉस्टल व खानपान की सुविधा, इंडस्ट्री विजिट और गैरट लेकर्स जैसी सुविधाएं दी जाती हैं। विशेष रूप से कुलिनरी और हार्स्पेटेलिटी जैसे ट्रेडों में उच्च गुणवत्ता की ट्रेनिंग पर जोर है। किचन लैब में कटिंग, कुकिंग, बेकिंग, फूड प्रेजेंटेशन, सर्विस मैनेजमेंट और मास्टरशेफ लेवल की ट्रेनिंग दी जाती है।

आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को बड़ा सहारा

कौशल कॉलेजों का सबसे मजबूत पक्ष यह है कि पूरी शिक्षा आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए पूरी तरह निशुल्क है। वहीं सक्षम छात्रों के लिए बैंक द्वारा लोन की भी व्यवस्था की गई है, जो विद्यार्थी खुद चुका देते हैं अब आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे भी अपने पढ़ाई का खर्च खुद उठा रहे हैं। प्रशिक्षण की पूरी लागत, यूनिफॉर्म, जूते, किट, किताबें और प्रैक्टिकल सामग्री, हॉस्टल व भोजन, करियर कंसलिंग, परीक्षा शुल्क सब कुछ सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। डेटा बताते हैं कि कौशल कॉलेज केवल दिखावे का प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि जमीन पर असरकारी मॉडल है।

एसएस प्लस टू हाई स्कूल के विद्यार्थियों ने तालाबंदी कर किया प्रदर्शन

RANCHI : शुक्रवार को एसएस प्लस टू हाई स्कूल बड़ो के 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों ने मुख्य परीक्षा के लिए उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होने से क्रोध होकर स्कूल के मुख्य द्वार पर तालाजड़ दिया और प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। छात्रों ने तालिका लिए छात्र लगातार स्कूल प्रशासन पर भविष्य के साथ खिलवाड़ का आरोप लगाते रहे। छात्रों का कहना है कि रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 13 दिसंबर। ऐसे में यदि उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो वे परीक्षा में कैसे शामिल हो पाएंगे। स्कूल प्रशासन ने छात्रों को समझाने की कोशिश की कि ताला खोलकर बातवीत के माध्यम से समाधान निकाला जा सकता है, परंतु छात्रों ने लिखित आश्वासन के बिना ताला खोलने से स्पष्ट इनकार कर दिया। स्थिति बिगड़ने से रूठे स्कूल की प्रिंसिपल हेनरी एता मिज ने शाना को सूचना दी।



स्वस्थ सब्जियां चाहिए तो नई तकनीक अपनाइए

देश में सब्जियों को उगाने और उसके बाद उन्हें बाजार तक ले जाने की प्रक्रिया की स्थिति बेहद खराब है। सब्जियों की फसलों पर अंधाधुंध और असुरक्षित तरीके से रसायनों का उपयोग करने से इनमें भारी मात्रा में कीटनाशकों के अवशेष बचे रह जाते हैं। यह इस प्रक्रिया में महज एक समस्या है लेकिन सबसे अहम समस्या। कुछ किसान और यहां तक कि सब्जियों के कारोबारी भी सब्जियों को ज्यादा दिन तक ताजा रखने के लिए उन्हें रसायनों में डुबोते हैं या उन्हें ग्राहकों के लिए ज्यादा आकर्षक बनाने की खातिर कलरिंग एजेंट लगाते हैं, जो उनमें पहले से मौजूद हानिकारक रसायनों की मात्रा में और बढ़ोतरी ही करता है।

इतने बड़े पैमाने पर रसायनों का प्रयोग करना स्वास्थ्य के लिए तो नुकसानदायक है ही बल्कि यह कीटनाशकों के प्रति कीटों की प्रतिरोधी क्षमता में भी इजाफा कर उन्हें ज्यादा आक्रामक बनाता है। यह मिट्टी और स्थानीय पर्यावरण में मौजूद सूक्ष्म जीवाणुओं को भी नष्ट करता है। कई सब्जियां खासतौर पर जमीन के नीचे उगने वाली सब्जियां मसलन गाजर और मूली को अक्सर नाले के पानी में धोया जाता है, जिससे उनमें जीवाणु आ जाते हैं। उर्वरकों का अंधाधुंध इस्तेमाल भी जमीन और भूमिगत जल को प्रदूषित करता है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण भी सुरक्षा नियमों और गुणवत्ता मानकों पर काम कर रही है, जो अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपनाए जा रहे स्वास्थ्य संबंधी और पौधों के स्वास्थ्य से जुड़े मानकों के आधार पर होंगे, जिससे सब्जियों का निर्यात बढ़ने में मदद मिलेगी। दूसरी ओर कृषि वैज्ञानिक भी सब्जियां उगाने के लिए पर्यावरण के अनुकूल तकनीक विकसित कर रहे हैं, जिनसे अगर पूरी तरह नहीं तो कम से कम काफी हद तक हानिकारक रसायनों के उपयोग को कम करने में मदद करेंगे। वाराणसी स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च (आईआईवीआर) ने ऐसी कई तकनीक पेश की हैं, जिनमें से कुछ जो सब्जी उत्पादकों के पास पहुंच भी चुकी हैं। ये

तकनीक कम लागत में बंपर फसल उत्पादन में मदद करती हैं और वह भी पर्यावरण और स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाए बिना।

सबसे अहम तकनीक है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट (आईपीएम), जो रसायन के कम से कम इस्तेमाल से फसल को बीमारी और विनाशकारी कीटों से बचाती है। इस प्रक्रिया में यह परिस्थितिकी और मिट्टी व जल जैसे प्राकृतिक संसाधनों को होने वाले नुकसान को भी कम करता है। आईपीएम के प्रमुख सिद्धांत सभी मामलों में एक जैसे होते हैं लेकिन उसके गहन तत्वों को खास सब्जी की फसल को जरूरत के हिसाब से ढाला गया है।

आईपीएम की प्रक्रिया में व्यापक तौर पर बड़ी बीमारियों और कीटों का रोध करने वाली फसलों के स्वस्थ बीजों का इस्तेमाल किया जाता है, जैविक संक्रमण नियंत्रण जीवाणुओं के साथ बीजों का प्रशोधन करते हैं, जड़ी-बूटियों और नुकसान नहीं पहुंचाने वाले अन्य सुशुद्ध उत्पादों का इस्तेमाल और कीटों के हमले से बचने के लिए फसल बुआई और कटाई का समय उसी हिसाब से तय करना। इसके अलावा किसानों को सलाह दी जाती है कि रोगाणु और कीटों के प्रजनन चक्र को तोड़ने के लिए वे सब्जियों की दो फसलों के बीच अनाज या कोई अन्य फसल लगाएं।

इसके अलावा आईआईवीआर लेकर आई है विभिन्न सब्जियों की कई किस्में, जिनमें बीमारियों और कीटों के लिए प्रतिरोधी क्षमता होती है। इनमें से कई किस्मों की उत्पादन क्षमता सामान्य किस्मों के मुकाबले 10 से 25 फीसदी ज्यादा है। इनमें से कुछ खासतौर पर लोबिया की काशी कंचन किस्म, भिंडी की काशी प्रगति और मिर्च की काशी अनमोल का उत्पादन इन फसलों की सामान्य किस्म के मुकाबले 20 फीसदी ज्यादा रहता है। खेतों से मिलने वाली खबरों के अनुसार इनमें से कुछ किस्मों को प्रीमियम पर बेचा जा रहा है। इसकी खामियां हैं कि कई बीज आपूर्तिकर्ता ऐसे बीजों की आपूर्ति कर रहे हैं, जो वास्तविक बीजों के मानकों पर खरा नहीं उतरते

हैं। इसलिए यह बेहद जरूरी है कि किसान विश्वसनीय स्रोतों से ही बीज की खरीद करें।

अन्य पर्यावरणनुकूल सब्जी उत्पादन तकनीकों में सबसे अहम हैं बुआई की शून्य जुताई' व कम से कम जुताई' और मिट्टी में पैदा होने वाले रोगाणुओं को मारने के लिए धूप दिखाना। कृषि विज्ञान व्यवहार मसलन पौधों के बीच में जरूरी दूरी रखना, जरूरत के मुताबिक ही सिंचाई करना, जमीन की नमी बचाने के लिए मिट्टी को पॉलिथीन या पौधों के अवशेष से ढकना (जिसे मल्लिंग कहते हैं), डिप सिंचाई और शैवाल नियंत्रण को भी विभिन्न फसलों के लिहाज से ढाल दिया गया है। इन तकनीकों के असर के अध्ययनों में सामने आया है कि शून्य जुताई' जिसमें स्थायी मेड़ पर सब्जियां बोई जाती हैं और बाकी खेत में पुरानी फसल का बचा हुआ हिस्सा ही लगा रहे, तो बुआई लागत में प्रति हेक्टेयर

18,000 रुपये की कमी आती है। इस तंत्र के तहत साल भर में डीजल की बचत का अनुमान प्रति हेक्टेयर 60 रुपये से ज्यादा है।

हालांकि आईआईवीआर इन तकनीकों को अपने और कृषि विज्ञान केंद्रों जैसे अन्य कृषि शोध संस्थानों के स्तर पर बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है लेकिन इसमें

सरकारी एजेंसियों का शामिल होना भी बेहद महत्वपूर्ण है। किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर इन तकनीकों का उपयोग पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के लिए तो बेहतर साबित होगा ही बल्कि इससे स्वयं किसानों और उपभोक्ताओं को भी काफी फायदा होगा।



हल्दी की उन्नत काश्त पद्धति से खेती

हल्दी एक महत्वपूर्ण मसाले वाली फसल है जिसका उपयोग औषधि से लेकर अनेकों कार्यों में किया जाता है। इसके गुणों का जितना भी बखाना किया जाए थोड़ा ही है, क्योंकि यह फसल गुणों से परिपूर्ण है इसकी खेती आसानी से की जा सकती है तथा कम लागत तकनीक को अपनाकर इसे आमदनी का एक अच्छा साधन बनाया जा सकता है। यदि किसान भाई इसकी खेती ज्यादा मात्रा में नहीं करना चाहते तो कम से कम इतना अवश्य करें जिसका उनकी प्रति दिन की हल्दी की मांग को पूरा किया जा सके। निम्नलिखित शास्त्र वैज्ञानिक पद्धतियों को अपना कर हल्दी की खेती सफलता पूर्वक की जा सकती है।

भूमि का चुनाव :

हल्दी की खेती बलुई दोमट या मटियार दोमट मृदा में सफलतापूर्वक की जाती है। जल निकास की उचित व्यवस्था होना चाहिए। यदि जमीन थोड़ी अम्लीय है तो उसमें हल्दी की खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है।

भूमि तैयारी



हल्दी की खेती हेतु भूमि की अच्छी तैयारी करने की आवश्यकता है क्योंकि यह जमीन के अंदर होती है जिससे जमीन को अच्छी तरह से भुरभुरी बनाया जाना आवश्यक है। मोल्ड बोल्ड प्लाऊ से कम से कम एक फीट गहरी जुताई करने के बाद दो तीन बार कल्टीवेटर चलाकर जमीन को अच्छी तरह से तैयार कर लेना चाहिए और इसमें पाटा चलाकर जमीन को समतल कर लें एवं बड़े ढेलो को छोटा कर लेना चाहिए।

खाद तथा उर्वरक :

20 से 25 टन /हे. के मान से अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद का उपयोग करना चाहिए क्योंकि गोबर की खाद डालने से जमीन अच्छी तरह से भुरभुरी बन जायेगी तथा जो भी रासायनिक उर्वरक दी जायेगी उसका समुचित उपयोग हो सकेगा। इसके बाद 100-120 कि. नत्रजन 60-80 कि. स्फुर 80-100 तथा कि./हे. के मान से पोटाश का प्रयोग करना चाहिए। हल्दी की खेती हेतु पोटाश का बहुत महत्व है जो किसान इसका प्रयोग नहीं करते है हल्दी की गुणवत्ता तथा उपज दोनों ही प्रभावित होती है। नत्रजन की एक



व्यवस्था होनी चाहिए।

खरपतवार नियंत्रण :

विशेष ध्यान रखना चाहिए हल्दी की खेती लगातार उसी जमीन पर न की जावे क्योंकि यह फसल जमीन से ज्यादा से ज्यादा पोषक तत्वों को खींचती

है जिससे दूसरे साल उसी जमीन में इसकी खेती नहीं करें तो ज्यादा अच्छा होगा। सिंचित क्षेत्रों में मक्का, आलू, मिर्च, ज्वार, धान, मूँगफली आदि फसलों के साथ फसल चक्र अपनाकर हल्दी की खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है।

विकसित किस्में :

मसाले वाली किस्म, पूना, सोनिया, गौतम, रशिम, सुरोमा, रोमा, ऋष्णा, गुन्डूर, मेधा, हल्दा1, सुकर्ण, सुगंधन तथा सी.ओ.1 आदि प्रमुख जातियां हैं जिनका चुनाव किसान कर सकते हैं। थोड़ी सी मात्रा यदि एक बार मिल जाती है तो फिर अपना बीज तैयार किया जा सकता है।

बुआई :

जिन किसान भाइयों के पास पानी की पर्याप्त सुविधा है वे अपरिल के दूसरे पखवाड़े से जुलाई के प्रथम सप्ताह तक हल्दी को लगा सकते हैं। लेकिन जिनके पास सिंचाई सुविधा का पर्याप्त मात्रा में अभाव है वे मानसून की बारिश शुरू होते ही हल्दी लगा सकते हैं किंतु खेती की तैयारी पहले से ही करके रखना चाहिए। जमीन अच्छी तरह से तैयार करने के बाद 5-7 मी., लम्बी तथा 2-3 मी. चौड़ी क्यारिया बनाकर 30 से 45 से. मी. कतार से कातर तथा 20 - 25 से.मी. पौध से पौध की दूरी रखते हुए 4-5 से.मी. गहराई पर गाठी कन्दों को लगाया चाहिए। इस तरह से हल्दी लगाने से 12 - 15 किंवटल हे. गाठों की जरूरत पड़ती है।

सिंचाई :

हल्दी में ज्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं है लेकिन यदि फसल गर्मी में ही बुवाई जाती है तो वर्षा प्रारंभ होने के पहले तक 4-5 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। मानसून आने के बाद सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती है। किंतु यदि बीच में वर्षा नहीं होती या कि सुखा पड़ जाता है तथा अक्टूबर के बाद यदि बारिश नहीं हो पाती है तो ऐसी परिस्थिति में 20-25 दिन के अंतराल पर सिंचाई करना आवश्यक हो जाता है। नवम्बर माह में पतितयों का विकास तथा धनकन्द की मोटाई बढ़ना आरंभ हो जाता है तो उस समय उपज ज्यादा प्राप्त करने हेतु मिट्टी चढ़ाना आवश्यक हो जाता है जिससे कन्दों का विकास अच्छा होता है तथा उत्पादन में वृद्धि हो जाती है।

जल निकास :

जल निकास का उचित प्रबंध करना चाहिए अन्यथा हल्दी की फसल पर विपरीत प्रभाव पड़ता है तथा पौधे एवं पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। अतः समय-समय पर वर्षा के ज्यादा पानी को खेत से बाहर निकालने की उचित

फसल चक्र :

हल्दी की सफल खेती हेतु उचित फसल चक्र का अपनाता अति आवश्यक है। इस बात का

कीट नियंत्रण :

आम तौर पर हल्दी में कीड़े की कोई ज्यादा समस्या नहीं देखी गई है कहीं-कहीं पर बेधक तथा थ्रिप्स (रस चुसने वाले कीटों की) की समस्या आती है। तना बेधक हेतु फोरेट थिमेट दो में से कोई एक दवा का 10 कि. हे के हिसाब से प्रयोग किया जा सकता है।

कटाई :

मई-जून में बोई गई फसल फरवरी माह तक खोदने लायक हो जाती है इस समय धन कन्दों का विकास हो जाता है और पत्तियां पीली पड़कर सूखने लगती हैं तथा समझना चाहिए कि हल्दी पक चुकी है तथा अब इसकी कटाई या खोदाई की जा सकती है। पहले पौधों के दरती हिसाए से काट देना चाहिए तथा बाद में हल से जुताई करके हल्दी के कन्दों को आसानी से निकाला जा सकता है जहां पर भी जरूरत समझी जाए कुदाली का भी प्रयोग किया जा सकता है। हल्दी की अग्रेती फसल 7-8 माह मध्यम 8-9 माह तथा देर से पकने वाली 9-10 माह में पककर तैयार हो जाती है।

उपज :

जहां पर उपरोक्त मात्रा में उर्वरक तथा गोबर की खाद का प्रयोग किया गया है तथा सिंचित क्षेत्र में फसल बोई गई है तो 50-100 किंवटल प्रति हे. तथा असिंचित क्षेत्रों से 50-100 किंवटल प्रति हे. कच्ची हल्दी प्राप्त की जा सकती है। यह ध्यान रहे कि कच्ची हल्दी को सूखाने के बाद 15-25 प्रतिशत ही रह जाती है।

उपचार (रवाइ) :

हल्दी को खोदते समय पूरी तौर से सावधानी बरतनी चाहिए जिससे धन कन्दों की कम हानि हो और समूची गांठें निकाली जा सकें गांठों को पहले छोटा-छोटा कर लिया जाता है इसके बाद बड़े-बड़े कड़हों में डालकर इसके उबाला जाता है। उबालते समय थोड़ा गोबर या फिर हल्दी की पत्तियों को ही पानी के साथ डालकर उबाला जाता है। ऐसा करने से रंग कुछ गहरा हो जाता है तथा हल्दी की गुणवत्ता बढ़ जाती है जिससे बाजार में भाव अच्छा मिलता है। लगभग 3-4 घंटे पकाने के बाद गांठें अंगुलियों की बीच दबाने पर आसानी से दब जाती है तो कड़हों से निकाल कर सूखने हेतु धूप में रखा जाता है जिससे गांठें अच्छी तरह से सूख जावें। इसके बाद किसी खुरदुरे चीज से गांठों को रगड़ कर साफ कर लिया जाता है बड़े पैमाने पर यह कार्य मशीनों पर किया जाता है और इस तरह से हल्दी की गांठें तैयार हो जाती है।

Rising influence of the Patrushevs in India-Russia ties

Bullets are bullish. The adage that war fills coffers is finally ringing true for India as the conflict in Ukraine is poised to enter its fourth year in less than three months. A single sentence in the 'outcome documents' released half-way through Russian President Vladimir Putin's visit to India on December 5 is pregnant with bullish possibilities. The description of this particular outcome hides more than it reveals—a memorandum of understanding that "entails cooperation in various sectors of maritime domain such as shipping, ports, joint mineral exploration, research and development". Two weeks before Putin's arrival in New Delhi, a visit to Goa by Nikolai Patrushev, chairman of Russia's Maritime Board, prepared the ground for what augurs to be the biggest military-industrial project to emerge from the 23rd annual India-Russia summit this month. The Maritime Board has identified Goa Shipyard as the base for production of frigates, corvettes, anti-mine and landing vessels as well as ice-breakers. Russia has also proposed continued production of Project 1135.6 class ships in Goa based on upgraded designs and state-of-the-art technology. Two such ships, Triput and Tavasya, based on Russian models, were launched for the Indian Navy in July last year and March this year, respectively. On November 20, the Russian foreign ministry's readout on Patrushev's visit quoted him as saying, "Our countries can jointly build up their own fleets, strengthen cooperation between them, establish robust and sanctions-resistant maritime logistics, and develop marine science and technology." The crux of the statement originated from grievances by head honchos of Goa Shipyard about delays in "material supply obligations" for collaborative naval projects with Russia. Both sides agreed that these challenges were because of "extraordinary global circumstances"—a euphemism for the war in Ukraine and supply chain disruptions. The current challenge on the strategic and commercial horizons for Russia's thriving shipbuilding sector is the Ukraine conflict. Midway through the war, Franco-British missiles supplied to Ukraine penetrated the defences of Russia's Black Sea fleet headquarters in Sevastopol, which was part of Ukraine until 2014. Major shipyards in Crimea have been affected by sanctions on supply of German engines and disruptions in getting ancillaries such as turbines from Ukraine.

If Goa Shipyard and Mormugao port become hubs for the activities of Russia's Maritime Board, ships could be built in Goa for Russia to at least partly compensate for production stoppages along the Black Sea, which is vulnerable to attacks from Ukraine. Patrushev was understandably guarded in his open meetings on Goa's maritime infrastructure. "The enterprise is subordinate to India's ministry of defence due to its military orientation, but we have very good prospects for cooperation," the authorised English translation of Patrushev's remarks said. The annual summit turned a new page in India-Russia engagement, which is best described as familial diplomacy. Patrushev, who has been by Putin's side as one of his most trusted aides since he became prime minister in 1999 and later president, is said to have an excellent chemistry with Prime Minister Narendra Modi. The two men met every time Patrushev came to India as secretary of Russia's Security Council, the equivalent of a national security adviser. In late September, as the groundwork for Putin's visit was under way, another Patrushev arrived in India—Deputy Prime Minister Dmitry Patrushev. He is Nikolai's son and was Russia's agriculture minister for six years before his promotion as deputy prime minister in charge of agriculture. During and after the visit, he initiated efforts to increase the market share of Indian shrimp products in Russia. The landed prices of Indian shrimp products in their biggest market, the US, have increased by 58 percent, thanks to the steep tariffs supplemented by anti-dumping duties.

THE Ramnath Goenka Memorial Lecture, delivered by Prime Minister Narendra Modi recently, has opened a Pandora's box regarding the enduring legacy Thomas Babington Macaulay left behind in India — his 'Minute on Education' (February 2, 1835) and the legal system framed in 1860 and later. The focus has not merely been on pedagogy, which is value-neutral, but also in terms of what the students imbibed as ideas and practices through printed literature and other sources.

The PM accused Macaulay of 'Shiksha vyavastha ka samool naash' (destruction of the education system), breaking the back of kaushal (skill), shattering self-confidence, throwing the entire knowledge system into the dustbin, condemning Indian heritage and culture instead of taking pride in them and rejecting local languages. All these developments produced an inferiority complex among Indians, he claimed. Blaming previous governments, particularly those of the Congress, the PM said these tendencies were concretised after Independence. It is indeed welcome that the Prime Minister is turning his attention to the state of education in the 12th year of his reign. Alas, the reality is not very bright. On October 19, 2020, addressing the centenary convocation of the University of Mysore, PM Modi highlighted the growth of higher education institutions such as IITs, IIMs, AIIMS and IIITs across the country during his rule. However, faculty appointments, admissions, funds and infrastructure as well as controversies regarding textbooks continue to cast dark shadows. The number of government schools has decreased (around 90,000 fewer between 2014-15 and 2023-24), while the number of private schools has gone up. These are serious imbalances.

As a Law Member of the Governor-General's Council of India, British historian, poet and Whig politician Macaulay claimed to have presented his Minute on education that changed the entire course of education in India. Addressing the Committee of Public Instruction, he based his argument on the central theme of the Charter Act of 1813 that set aside a sum "for the revival and promotion of literature and the encouragement of the learned natives of India, and for the introduction and

A red herring called Macaulay

India should focus on an education system that fosters scientific temper and creates an inclusive society

promotion of a knowledge of the sciences among the inhabitants of the British territories." However, it is doubtful whether he said what is being attributed to him: "I have travelled across the length and breadth of India... I propose that we replace her old and ancient education system, her culture, for if the Indians think that all that is foreign and English is good and greater than their own, they will lose their self-esteem, their native culture and they will become what we want them, a truly dominated nation." That's because on February 2, 1835, he was in Calcutta, not in London.

Indeed, in referring to "the learned natives of India", he set



the tone for racial superiority even before he came to his central argument. The essential argument of his Minute was regarding not wasting public money on education in 'Sanskrit' and Persian. He stressed spending public funds on an education system that imparted education in science and the contemporary knowledge system in the West in English.

He mentioned in the document: "I would strictly respect all existing interests. I would deal even generously with all individuals who have had fair reason to expect a pecuniary provision. But I would strike at the root of the bad system which has hitherto been fostered by us. I

would at once stop the printing of Arabic and Sanscrit books, I would abolish the Madrasa and the Sanscrit College at Calcutta. Benares is the great seat of Brahmanical learning; Delhi, of Arabic learning. If we retain the Sanscrit College at Benares and the Mahomedan College at Delhi, we do enough, and much more than enough in my opinion, for the eastern languages." He further said: "If the Benares and Delhi Colleges should be retained, I would at least recommend that no stipends shall be given to any students... The funds which would thus be placed at our disposal would enable us to give larger encouragement to the Hindoo College at

Calcutta, and to establish in the principal cities throughout the Presidencies of Port William and Agra schools in which the English language might be well and thoroughly taught." He argued that a lac (lakh) rupees granted by the Government of India must not be wasted on scholarship for the students of 'Sanskrit' and Persian and on the publication of books in these languages, since the books in English sold more. Then came his aim, "We must at present do our best to form a class who may be interpreters between us and the millions whom we govern; a class of persons, Indian in blood and colour, but English in taste, in opinions, in morals, and in intellect". Further, his pithy remark, "a single shelf of a good European library was worth the whole native literature of India and Arabia", indeed offends us as Indians.

Howsoever racist Macaulay must have been, the statement above sounds more from the pen of an administrator, contemplating a utilitarian logic for the fund having been allocated for education.

The colonial administration he represented stood for extracting resources for the metropolis, not for charity. We should ask ourselves in the same spirit: did it harm us? I will conclude with two personal experiences with two generations. A product of Macaulian education from my parents' generation, a doctor was well-versed in Urdu, but he quickly learnt administrative Hindi. My father, an officer in the Bihar Police, had proficiency in English, Hindi and Sanskrit. Beginning my education in Bihar, I found that Hindi-medium textbooks inculcated nationalism. Instead of drawing a red herring, we should keep building and refining an education system that is modern, contemporary, fosters scientific temper and creates an inclusive society.

A debate on reforms that delivered only rancour

What might have been a sober discussion in Lok Sabha on systemic reform slid into a point-scoring exercise between the home minister and the leader of opposition

The two-day Lok Sabha debate on electoral reforms should have been an opportunity to clarify procedures, strengthen transparency, and reaffirm institutional neutrality at a time when public trust in democratic processes is increasingly brittle. Instead, it descended into a familiar political joust between the Leader of the Opposition Rahul Gandhi and Union Home Minister Amit Shah—each armed not only with arguments, but with history, grievance, and sharp-edged jibes. Rahul Gandhi levelled a sweeping charge of "institutional capture", accusing the Election Commission of operating without accountability and alleging "vote chori" through opaque voter-roll practices, questionable deletions under the ongoing Special Intensive Revision, and a lack of transparency in electronic voting machines' architecture. He demanded machine-readable electoral rolls, full technical disclosure of EVMs, access for parties to examine them, protection of CCTV evidence, and removal of immunities shielding election commissioners. His warning—that a future government would "change the law retrospectively"—was as much political



messaging as it was a call for reform. Amit Shah's rebuttal was equally political. He dismissed the opposition's claims as "manufactured narratives", arguing that SIR is a constitutional exercise conducted by the Election Commission independent of the government. When pressed on alleged voter-roll manipulation, he countered with the question of whether "infiltrators" and non-

citizens should remain on electoral rolls—reframing the debate around national security rather than institutional procedure. He invoked historical episodes to turn the "vote chori" charge back at the Congress, citing precedents from the Nehru, Indira, and Sonia eras to argue that the opposition lacked moral authority to lecture on electoral integrity.

What might have been a sober discussion on systemic reform slid into point-scoring. Gandhi's narrative of democratic erosion met Shah's counter-narrative of Congress's past failings. Allegations of voter manipulation were matched with charges of protecting "ghuspathiyas". Both leaders ended up appealing more to their constituencies than to the substance of electoral reform. And yet, the core question remains urgent: India needs a credible, transparent, error-free system of electoral roll revision, robust auditability, and institutional safeguards that command cross-party trust. Without concrete steps—legislative clarity, procedural reforms, or independent oversight—the debate risks becoming another episode of political theatre. Democracies weaken not only by manipulation, but also by neglect.

The contradictions in offering privileges to extradite fugitives

True moral authority lies not in appealing foreign courts for extraditing prominent economic fugitives, but in ensuring equal dignity for all those behind bars. Former European colonisers' demands on this count reveal double standards. An update of our extradition law is overdue

European courts seem keen to legitimise high privileges for other countries' economic fugitives. Belgian courts have reportedly approved the extradition of one of India's most wanted economic fugitives only after the Indian government furnished formal, legally-binding assurances. The government undertook to lodge him in a specially-prepared cell at Mumbai's Arthur Road Jail, conforming to the standards set by the European Committee for the Prevention of Torture—adequate space, ventilation, medical care, nutritious food, media access, and no solitary confinement.

Demands for special privileges are understandable when sought for a country's own citizens. But insistence on such treatment for those wanted elsewhere is discordant. The trend reflects a newfound love of some countries for wealthy economic fugitives. Oliver Bullough's 2022 bestseller, *Butler to the World: How Britain Became the Servant of Tycoons, Tax Dodgers, Kleptocrats and Criminals*, lucidly captures this phenomenon and its corrosive effects. Every individual, including an accused or a convict, is entitled to basic human rights. But demanding special comforts under the guise of human rights reflects troubling double standards and a transactional stance to justice. Using it as an excuse to embrace a fugitive moneybag's assets is an open endorsement of financial crimes. This is paradoxical especially because many of these countries are founding members of the Financial Action Task Force and signatories to global conventions against money laundering. Their offshore tax havens further expose this hypocrisy. Unless such duplicity is confronted, global public policy's fight against financial crimes and money laundering risks becoming an empty slogan. Their own

histories offer reminders of these contradictions. Many European countries abolished barbaric prisons barely a century ago. Dismemberment, whipping, and long incarcerations, even for minor offences, were once common. Recall the hero in Victor Hugo's *Misérables* (1862), an impoverished man imprisoned for 18 years for stealing a loaf of bread. In European colonies, nationalist leaders were left to rot in jails with appalling conditions. Yet, those nations now advocate exalted human rights for criminals from other countries, often to the point of obstructing justice itself.

Almost all the major prisons in India were built by the British, primarily to incarcerate freedom fighters. The Cellular Jail in the Andamans was the most notorious. Others such as Alipore Jail in Kolkata, Naini Jail in Prayagraj, and Yerawada Jail in Pune also served as sites of confinement and torture for countless nationalist leaders. Built in 1926, Arthur Road Jail in Mumbai continues to function as the city's central prison. It houses a mix of inmates—business leaders, public officials, celebrities, and political figures—with some of them housed in upgraded cells. The need to offer case-specific assurances to foreign courts stems from the presumption that India's prisons do not meet minimum humanitarian standards. This raises a deeper moral and institutional concern: why should humane treatment be an exception, invoked only when international scrutiny

demands it? A constitutional democracy governed by the rule of law must guarantee humane detention for every person, irrespective of nationality, status, or offence. Ensuring the minimum standards universally, rather than selectively, would enhance the credibility of the justice



system and obviate the need for external assurances in extradition proceedings. If India provides superior detention conditions to extradited fugitives while ordinary prisoners continue to endure substandard or overcrowded facilities, it raises a serious question of discriminatory treatment. Domestic prisoners could justifiably argue that such selective privileges violate the constitutional guarantees of equality and the right to life

with dignity. The State cannot defend this disparity solely on the grounds of diplomatic expediency or international image. India's limited success in securing the return of wanted persons has been a result of adroit diplomatic and legal efforts, rather than the strength of its extradition law. The Extradition Act, 1962 is out of sync with contemporary global realities. It largely reflects the older paradigm of extradition centred on political offenders and non-financial crimes, discouraging the former while facilitating the latter. Despite amendments in 1993, the law does not adequately address the challenges posed by financial globalisation, India's own economic liberalisation, the rise of transnational financial crimes, offenders' increasing ease in crossing borders, and the growing practice of states offering expedited citizenship in exchange for investment.

The Extradition Act is also oblivious to the stonewalling tactics by many Western nations. While India imposes no restriction on the extradition of its own nationals and has been accommodative on such matters, most other nations rarely reciprocate. They often refuse to extradite their own citizens to India and are increasingly becoming intransigent in extraditing even third-country nationals involved in economic offences or other serious crimes.

India's extradition framework must be strengthened and treaties redrawn to reflect evolving global dynamics and India's growing international stature. A robust legal and diplomatic strategy, supported by credible, universal prison reforms, would enable India to negotiate from a position of strength and ensure that all fugitives are brought to justice under Indian law.

New labour codes: No, your take-home salary isn't reducing. Here's the math

New Delhi.(Agency)

Ever since the new labour codes were notified on November 21, 2025, many salaried employees have been worried that their take-home pay would shrink. Much of the anxiety came from the rule that basic pay and related components must form at least half of the total salary. The assumption was simple: if basic pay rises, provident fund deductions rise, and the in-hand salary falls. The Ministry of Labour and Employment has now made it clear that this fear is misplaced. Officials said on Wednesday that the new codes do not automatically reduce anyone's take-home salary. The key reason lies in how PF is actually calculated. SALARY CALCULATION MATH EXPLAINED

Even if an employee's basic pay increases under the new wage structure, PF contributions will continue to be calculated on the existing statutory ceiling of Rs 15,000 unless both the employer and employee voluntarily choose a higher base.

This ceiling is what matters for most salaried workers. As long as PF is capped at Rs 15,000, the monthly deduction remains unchanged. The ministry highlighted that nothing in the new law forces PF to be calculated on the full salary. To make this clearer, the ministry shared a simple example. Consider an employee with a monthly salary of Rs 60,000. If Rs 20,000 counts as basic pay and dearness allowance and the remaining Rs 40,000 is paid as allowances, PF will still be calculated on Rs 15,000 so long as the employee has not opted for a higher PF base. Under the old rules and the new codes, the PF contribution remains the same. The employer contributes Rs 1,800 and the employee contributes Rs 1,800, leaving the take-home salary unchanged at Rs 56,400.

This explanation has offered relief to many anxious employees who thought the new wage definition would automatically shrink their disposable income. The ministry said the purpose of the revised structure is to bring uniformity and clarity, not to reduce salaries.

UDIN prevented Rs 80,000 crore frauds since 2019: ICAI

NEW DELHI.(Agency)

Ever since India adopted the Unique Document Identification Number (UDIN) for certifications, GST and tax audit reports by practicing Chartered Accountants, the country has prevented frauds worth Rs 80,000 crore, claims Institute of Chartered Accountants in India (ICAI). ICAI president Charanjot Singh Nanda informed the media on Friday that UDIN is first of its kind initiative globally, and it has prevented unauthorized individuals from misusing a CA's name, signature, or membership details, eliminated the risk of fraudulent certifications and strengthened the integrity and reputation of the profession. He says that the initiative has received global attention with ICAI equivalent institutions and bodies from many countries seeking help from ICAI for implementing a similar system. UDIN was implemented in August 2019, and since then over 10 crore UDINs have been generated. To curb the malpractices of non-CAs falsely presenting themselves as CAs and authenticating documents, ICAI introduced the Unique Document Identification Number (UDIN), an 18-Digits system generated unique number for every document certified/attested by full time practicing Chartered Accountants.

Gold Edges Higher To Rs 1,32,599 Per 10 Grams, Silver Slips After Record High

Mumbai.(Agency)

Gold prices inched up on Friday morning, while silver slipped as traders booked profits after the metal hit a fresh record high on the MCX.

During early trade, MCX gold futures for February were trading 0.10 per cent higher at Rs 1,32,599 per 10 grams. "MCX Gold has broken out to lifetime highs, trading near Rs 1,32,776 inside a tightening ascending wedge with firm support at Rs 1,31,400," analysts stated. The next resistance zone opens the momentum leg toward Rs 1,34,000 and above," they added. In contrast, MCX silver futures for March were down 0.50 per cent at Rs 1,97,951 per kg. In the previous session, silver had touched an all-time high of Rs 1,98,814 per kg and ended the day with a strong 5.33 per cent gain at Rs 1,98,799. Gold February futures also saw healthy buying, closing at Rs 1,32,469 per 10 grams after rising 2 per cent. Both metals rallied after the US Federal Reserve cut its benchmark interest rate by 25 basis points and hinted at the possibility of another rate cut next year. The dollar index also slipped to 98.30 -- making gold cheaper for global buyers and boosting demand. At the same time, the Indian rupee continued to remain at its record low against the US dollar. The weaker currency is supporting gold prices in the domestic market. Investors are now waiting for key US data, including inflation numbers and the non-farm payrolls report due next week. These indicators will help shape expectations around the Fed's next policy moves. "The US Federal Reserve's decision to cut key interest rates by 25 bps to 3.50 per cent-3.75 per cent amid persistent inflation has reinforced bullish sentiment in precious metals," market watchers stated. Lower rates reduce the opportunity cost of holding non-yielding assets like gold and silver, attracting fresh investment flows. With bullion already at record highs, this policy shift adds momentum to the rally, as investors seek safe-haven assets amid economic uncertainty and inflationary pressures," analysts mentioned.

NPS expands investment options: Now gold, silver ETFs and Nifty 250 picks allowed

India's pension regulator issues updated unified investment rules for pension schemes, introducing clearer limits and a wider range of asset classes.

New Delhi.(Agency)

The National Pension System (NPS) is set to become more flexible and potentially more rewarding after the pension regulator opened the door to new investment options. In a major update, the Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) has allowed NPS, the Unified Pension Scheme (UPS) and the Atal Pension Yojana (APY) to invest in gold and silver exchange-traded funds, the Nifty 250 index and select Alternative Investment

Funds. The changes were announced through a new master circular issued on December 10, 2025. The circular replaces several older guidelines and lays out fresh rules on how pension money can be invested across equity, debt, short-term instruments, ETFs and other approved schemes.

A WIDER RANGE OF INVESTMENTS
One of the biggest changes is the inclusion of gold and silver ETFs. This marks the first time NPS schemes can take exposure to precious metals, which are often seen as a hedge during uncertain times. The circular also allows investments in the Nifty 250 index, giving pension funds access to a broader range of companies beyond the largest firms in the market. The circular further permits limited investments in Category I and II Alternative Investment Funds. These funds invest in areas such as start-ups, infrastructure and other long-term sectors, offering an additional source of growth.

CLEAR LIMITS ON DIFFERENT ASSET

CLASSES

Government securities remain the mainstay of NPS and APY portfolios, with a maximum limit of 65%. This includes



central and state government bonds, PSU bonds and gilt mutual funds. The aim is to keep a large portion of pension savings in safe and stable assets.

Corporate debt can make up to 45% of the portfolio. This category includes well-rated corporate bonds, Basel III instruments, rupee-denominated bonds from global institutions and bank

deposits. Strict credit rating requirements are in place to ensure quality.

Equity investments are capped at 25%. Pension funds can now invest in stocks forming part of the Nifty 250 index, along with select BSE stocks. Most equity exposure must stay within the top 200 companies by market size.

STRONG RISK CONTROLS

To protect pension money, the regulator has retained strict rules on concentration. No single industry can account for more than 15% of total assets, and exposure to individual companies is tightly capped.

Similar limits apply to REITs and InvITs.

WHAT IT MEANS FOR SUBSCRIBERS

These changes are expected to make NPS more balanced and future-ready. With new options like gold, silver and a wider equity basket, subscribers may benefit from better long-term growth while still enjoying strong risk control.

Keys to new homes first, then redevelopment begins: Pranav Adani on Dharavi plan

New Delhi.(Agency)

Pranav Adani, Managing Director of Agro and Oil & Gas at the Adani Group, outlined key details of the ambitious Dharavi redevelopment project during his first TV interview on Agenda AajTak. He described the initiative as one of the most significant urban transformation projects currently underway and addressed major concerns around relocation and rehabilitation. Adani highlighted that the company's approach is to build new homes for existing residents first and hand over their house keys before any redevelopment work begins on their current settlements. "First, we will build your house, we will give you the keys, you will move into the final house first, and then only we will break your slum and do the redevelopment," said Adani. He mentioned that despite several past attempts over the past four decades, Dharavi's redevelopment never moved forward. This time, he said, the project is finally progressing with a concrete plan to build around 200,000 new homes, ensuring residents are moved into these units before any demolition

or redevelopment of old structures begins. Under the government's rehabilitation policy, those who have lived in Dharavi since before 2000 will receive new homes within the redevelopment area. Those who moved in after 2000 will be offered alternative



housing options elsewhere in Mumbai. Adani acknowledged that one of the biggest fears among residents is whether they will actually receive new homes if they vacate their existing ones. Reiterating the company's commitment, he said the keys to new houses will be handed over before any resident is asked to move, a step aimed at building trust and avoiding forced

evictions. The redevelopment plan also includes modern infrastructure, improved connectivity, and a "multi-model development" strategy. A detailed blueprint is already in motion, and work has begun on various components of the project. Beyond Dharavi, Adani spoke about broader infrastructure needs in Mumbai, including the requirement for more airports to match global city standards. He also discussed the group's ongoing and upcoming projects in states like Assam, where airport and infrastructure development is underway. He highlighted business opportunities in Bihar as well, praising the ambition of the state's youth. He pointed to investments by the Adani Group in areas such as smart meters and cement manufacturing as part of a wider push to support economic growth in the state. On the subject of artificial intelligence, Adani predicted that AI will soon become deeply integrated into daily life. Instead of reducing jobs, he said.

Mexico to impose up to 50% tariff on Indian exports

NEW DELHI.(Agency)

As India is still navigating ways to recover from the US tariff heat, Mexico has also slapped a steep tariff on several Indian items. Mexico's Congress has approved a bill that seeks to impose higher tariffs up to 50% on imports from India, China, Brazil and several other countries who are not having free trade agreements with the country. The tariff will take effect on January 1, 2026, after the lower house approves it. The tariff will be imposed on items like auto parts, light vehicles, plastic, toys, textiles, furniture, footwear, clothing, aluminium and glass. The proposed tariffs will range from 5% to 50%. The automobile sector is going to be the worst-hit as Mexico is India's third-largest car export market after South Africa and Saudi Arabia. India's total export to Mexico stood at \$5.7 billion



in 2024-25 with a trade surplus of \$2.8 billion. India's trade surplus with the country has gone up by nearly 12 times from 0.24 billion in 2020-21 to \$2.87 billion in 2024-25. Mexico's new tariffs on Asian imports are broadly aligning with US efforts to tighten trade barriers against China, along with other Asian nations. The Society of Indian Automobile Manufacturers, an industry group that includes representatives of car exporters like

VW, Hyundai and Suzuki among its members, had previously urged India's commerce ministry in November to press Mexico to "maintain status quo" on tariffs for vehicles shipped from India, Reuters reported. Even export bodies like the Engineering Exports Promotion Council (EEPC) had written to Commerce Minister Piyush Goyal asking him to begin talks with Mexico on a potential FTA to mitigate the risk of the US tariff. "We have also proposed FTAs with key Latin American countries such as Chile, Peru, and Mexico to get duty-free market access. This will also help us to de-risk from the US," Pankaj Chadha, Chairman, EEPC India, had said. The proposed bill by the Mexican government also include textile sector that could face high tariffs.

guide for brands, investors and advisers trying to understand this fast-changing world. The index shows a steady rise in luxury prices, climbing 22% between 2022 and 2025. This works out to an annual increase of 6.7%, driven by strong demand across lifestyle and real estate categories. WELLNESS TAKES CENTRE STAGE

One of the most noticeable trends is the rise of wellness retreats. Places like Amanbagh and Ananda have become preferred escapes for the ultra-rich, pushing the wellness category up 14.3% annually since 2022. Longevity, mental health and personalised therapies are becoming central to how the wealthy choose to spend their time and money.

EXPERIENCES OVER POSSESSIONS

Exclusive experiences, whether cruising through Antarctica or dining at top global restaurants, are now more valuable to many than physical assets. This category has grown 11.6% each year since 2022, showing a clear preference for memories rather than material items.

LUXURY REAL ESTATE AND FASHION STAYSTRONG

Branded residences equipped with smart technology continue to be a status symbol, rising 10.8% annually.

Price Of LPG Cylinder In India Vs Pakistan, Sri Lanka, Nepal: How Much Do Customers Have To Pay

In a written reply to a question in the Lok Sabha, Petroleum and Natural Gas Minister Hardeep Singh Puri tabled data showing the effective price of a 14.2 kg LPG cylinder in India.

New Delhi.(Agency)

The price of LPG for consumers in India is much lower than in neighbouring Pakistan, Sri Lanka, and Nepal, Petroleum and Natural Gas Minister Hardeep Singh Puri informed the Parliament on Thursday.

In a written reply to a question in the Lok Sabha, the minister also tabled data showing that the effective price of a 14.2 kg LPG cylinder as on November 1 this year in India (Delhi) was Rs 553 for PMUY beneficiaries, while in the case of regular consumers, the price was Rs 853. This is much lower than the prevailing



prices in neighbouring Pakistan (Lahore) at Rs 902.20 per cylinder, Sri Lanka (Colombo) at Rs 1,227.58 and Nepal (Kathmandu) at Rs 1,205.72. India imports about 60 per cent of its LPG requirement, and accordingly, prices of LPG in the country are linked to its prices in the international market. While the average Saudi CP (international

benchmark for LPG pricing) rose by 21 per cent from US\$ 385/MT in July 2023 to US\$ 466/MT in November 2025, the prices of domestic LPG were reduced by about 22 per cent from Rs. 1,103 to Rs. 853 during this period, the minister said. He said that for FY 2025-26, the government is providing a targeted subsidy of Rs 300 per 14.2 kg cylinder for up to 9 refills of a

14.2 kg cylinder to the PMUY consumers. For PMUY consumers, the effective price for domestic LPG has been reduced by about 39 per cent from Rs 903 in August 2023 to Rs 553 in November 2025.

As a result of various steps taken by the government to improve the affordability of domestic LPG for PMUY consumers, per connection consumption of PMUY beneficiaries (in terms of the number of 14.2 kg LPG cylinder refills taken per year) has increased from 3.68 (FY 2021-22) to 4.47 in FY 2024-25.

In order to provide more LPG for cooking in rural and remote areas, oil marketing companies (OMCs) have commissioned 8,017 distributorships, from April 1, 2016, to October 31, 2025, across the country, out of which 7,420 (i.e. 93 per cent) are catering to rural areas. As of November 1 this year, there are a total of 25,587 LPG distributorships across the country. These are served through 214 LPG bottling plants of OMCs located across the country. As a result of these efforts, LPG coverage in the country has improved from 62 per cent in April 2016 to near saturation now, the minister added.

Come June, Delhi University's Veer Savarkar College to start ops. What will it offer?

The last time that DU had set up a new college was in 1995, when Bhaskaracharya College of Applied Sciences had been established, funded by the Delhi government.

New Delhi.(Agency)

Undergraduate programmes in Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning (ML), Data Science, Entrepreneurship and Development: these are the three industry-aligned courses that Delhi University's Veer Savarkar College—the varsity's first new college in three decades—located in South West Delhi's Najafgarh is set to offer in the next academic year, The Indian Express has learnt.

While the B.Sc (Hons) in Data Science and B.Sc (Hons) in AI and ML programmes will offer 120 seats each, the student capacity for the BBA in Entrepreneurship and Development degree will be limited to 60 seats. Meanwhile, a proposal to create

around 60 teaching posts for the new institution has reached the final stage of approval, an official familiar with the process said. "The construction of the college is about 30% completed and will be ready to open in June 2026, before the next academic cycle begins," the official added.

Admissions to the college were originally slated to begin this summer, following a March announcement by Vice-Chancellor Yogesh Singh during DU's 92nd annual court meeting. During that meeting, he had said that the institution would start enrolling students in the 2025-26 academic session. However, procedural holdups stalled the admission process.

By August, senior DU officials told that key approvals from the Ministry of Education



and the Ministry of Finance were still pending, eventually delaying the progress on faculty recruitment and academic planning.

The last time that DU had set up a new college was in 1995, when Bhaskaracharya College of Applied Sciences had been established, funded by the Delhi government.

As per a DU statement issued in March, Veer Savarkar College at Roshanpura village in Najafgarh is set to be developed at a cost of Rs 140 crore.

The college will have 24 classrooms, eight tutorial rooms, 40 faculty offices, as well as department libraries, conference facilities, and a canteen, spread over a built-up area of 18,816.56 sq m. It will reserve two seats in each course for applicants from Roshanpura village, which had donated land for the college.

One seat will be reserved for women.

In January, Prime Minister Narendra Modi had laid the foundation stone for Veer Savarkar College, alongside two other major infrastructure projects for the varsity — a new campus in Surajmal Vihar and another in Dwarka. Together, these projects represented a combined investment of over Rs 600 crore, intended to modernise and expand DU's academic footprint. The Eastern Campus in Surajmal Vihar, spanning 15.25 acres, will cost Rs 373 crore and house programmes such as LLB, LLM, and multi-disciplinary courses. Facilities will include modern classrooms, moot courts, computer labs, and cafeterias.

After crackdown on gangs extorting traffic cops in Delhi, Special CP asks officers to report blackmail attempts

New Delhi.(Agency)

In the wake of police busting two gangs involved in extorting traffic police personnel, Special Commissioner of Police (Traffic) Neeraj Thakur has encouraged officers to report blackmail attempts by individuals.

To this effect, the Special CP has instructed the Deputy Commissioner of Police (Traffic) to hold Sampark Sabhas—formal meetings led by senior police officers to address the grievances of junior personnel—to motivate officers to come forward and report any attempts to extort money from them. These instructions were issued during a meeting chaired by Special CP Thakur on December 4.

On Wednesday, the police said that they had arrested five men in connection with the syndicate, adding that the two gangs had acquired crores of rupees from commercial vehicle drivers and by blackmailing traffic police personnel. The first arrests in the case were made in the last week of November.

The probe revealed that the accused were actively running parallel systems. One gang sold fake stickers to commercial vehicle drivers for Rs 2,000 to Rs 5,000 per month to bypass entry-point restrictions, while another extorted money from traffic police personnel by fabricating videos of them performing their duties.

According to police, officers are also probing the role of some Traffic Inspectors (TIs) who allegedly assisted the gang and even took a share of the extorted money. The meeting also included discussions on ensuring minimum inconvenience to the general public during VIP movements. The Special CP directed that traffic should be halted only for the minimum duration necessary for security arrangements.

Delhi's school fee law kicks in: 3 tier-system in place, parents can file complaints with 15% backing

New Delhi.(Agency)

Four months after the Delhi Assembly passed the Delhi School Education (Transparency in Fixation and Regulation of Fees) Bill, 2025, to regulate fees in private schools amid protests by parents over arbitrary hikes, the Delhi government officially notified the Act on Wednesday with Lieutenant-Governor V K Saxena issuing the Gazette notification, The Indian Express has learnt.

At the centre of the new regime is a three-tier committee structure—a School-level Fee Regulation Committee, the District Fee Appellate Committee, and the Revision Committee. Another key aspect of the Act is that a complaint to the District-level Committee must be backed by at least 15% of the affected parents. The Act makes parents a part of the decision-making process.

However, parent associations had previously raised concerns over the 15% threshold, arguing that it may be difficult to mobilise support, but the mechanism remains intact in the notified rules and now has a codified appeal format and scrutiny process.

Under the new Act, "private unaided recognised schools are strictly prohibited from collecting any fees that are not explicitly defined and sanctioned". The Act brings under its ambit over 1,500 private unaided schools in the Capital after years of protests by parents.

"All permissible fees must be itemised and disclosed as distinct components," reads Chapter II of the Act, which categorically prohibits the collection of "excess fee". The defined fee heads include admission charges, registration charges, security deposit—all of which are non-recurring charges.

Tuition fees have been defined to include "standard establishment costs and expenditures directly related to curricular activities". It cannot be used to recover capital expenditure, including investments for infrastructure development or any other non-revenue generating assets, according to the Act. Apart from this, term fees, annual charges and development fees have also been defined under the Act.

Birth to death services under one roof: How Delhi's expansion to 13 districts makes citizen lives easier

Under the new plan, the city gets three new districts — Outer North, Central North and Old Delhi. Meanwhile, areas under Shahdara district have been redistributed in Northeast and East districts.

New Delhi.(Agency)

In a major overhaul, the Delhi government has approved a revamp of the Capital's administrative structure, reorganising its 11 revenue districts into 13 with an aim to improve coordination and speed up delivery of public services. The new districts will be aligned with the city's 12 municipal zones, along with the New Delhi Municipal Corporation (NDMC) and Delhi Cantonment Board.

The move aims to enhance ease of living for citizens with an increase in the number of sub-divisional and sub-registrar offices as well as establish mini secretariats in all the districts. "This reform will significantly speed up delivery of public services, and ensure seamless coordination for land records,

property registration, civic services, and grievance redressal for citizens," a spokesperson for the Delhi government said.

The Capital currently has 11 revenue districts, headed by respective district magistrates, while the city is divided into 12 MCD zones, led by respective deputy commissioners. Under the new plan, the city gets three new districts — Outer North, Central North and Old Delhi. Meanwhile, areas under Shahdara district have been redistributed in Northeast and East districts.

The gazette notification for the redrawing of boundaries will be issued within 15 days and the reorganisation will be completed by the end of this month, said officials. The government has sanctioned a budget of Rs 25 crore for the move.

Ease of living in focus, Delhi now has 13 districts in major revamp

CM Rekha Gupta termed the decision as a "historic" step towards adapting Delhi's administrative system to the requirements of the 21st century. Gupta added that in a metropolis like Delhi, smaller, balanced, and administratively empowered districts are necessary for improved coordination of services, faster grievance redressal, and effective monitoring.

All of these districts will also have a mini secretariat, where citizens will be able to access numerous services such as revenue offices, and sub-registrar offices at a single location. The number of sub-divisions have also been increased from existing 33 to 39 and sub-registrar offices increased from 22 to 39.

Gangster Lagarpuria, aide convicted under MCOCA

New Delhi.(Agency)

Notorious gangster Vikas Lagarpuria and his associate Dhirpal have been convicted under the stringent Maharashtra Control of Organised Crime Act (MCOCA) act for running an organised crime syndicate—nearly a decade after they were first booked for the same. The judgment was announced on Wednesday by Additional Sessions Judge Vandana Jain in Dwarka court.

In an order dated December 10, the court said, "...both the accused persons namely Vikas Gulia alias Vikas Lagarpuria and Dhirpal alias Kana are convicted under Section 3 of MCOCA. However, the court acquitted the duo

under Section 4 (punishment for possessing unaccountable wealth on behalf of a member of an organised crime syndicate) of MCOCA.



Lagarpuria, known as the leader of the Vikas Lagarpuria gang, is involved in as many as 18 criminal cases including that of murder, attempt to

murder, extortion, robbery, house trespass, and criminal intimidation etc registered at various police stations at Delhi and Haryana.

The first case against him was lodged in 2012 at Chawla police station. The same year, Vikas was booked under Section 3 (punishment for organised crime) of MCOCA at Nazafgarh police station.

Lagarpuria was arrested by the Delhi Police in 2022, after absconding for years in Dubai. Langarpuriya was also involved in the 2021 Rs 30 crore heist at the offices of Alpha G Corp Management Services in Sector 84 in Gurgaon. He is currently lodged in Mandoli jail while Dhirpal stays in Rohini jail.

Akhlaq lynching case: Court to now hear UP govt's petition to drop charges against accused on Dec 18

The defendant lawyer, Yusuf Saifi, told the court that he wanted to file an objection to the govt's application

New Delhi.(Agency)

A fast-track court in Surajpur will now hear on December 18 the Uttar Pradesh government's application to withdraw charges against all 19 accused in the 2015 lynching of Mohammad Akhlaq after the prosecution's lawyer sought to argue the case.

Nearly a decade ago, Akhlaq (50) was lynched by a mob over rumours of alleged cow slaughter and storing its meat at his home in Dadri's Bisada village.

The court had reserved the case for December 12 after the government moved the application to withdraw prosecution against the accused.

On Friday, the defendant lawyer, Yusuf Saifi, told the court that he wanted to file an objection to the UP government's application for withdrawal.

Speaking to The Indian Express, Saifi said, "We submitted an application for more time and now the matter is listed for

December 18."

On September 28, 2015, a mob gathered outside Akhlaq's house after an announcement from the village temple alleged that he had slaughtered a cow. Akhlaq and his son Danish, who tried to intervene, were dragged out of their home and assaulted until they fell unconscious.

Akhlaq later died at a Noida hospital, while Danish survived after suffering severe head injuries and undergoing major surgery.

Police had registered an FIR at Jarcha police station under IPC sections 302 (murder), 307 (attempt to murder), 147 (rioting), 148 (rioting with deadly weapon), 149 (unlawful assembly), 323 (assault), 504 (intentional insult to disturb peace), among others, based on a complaint by Akhlaq's wife, Ikraman.

Police filed the chargesheet on December 23, 2015, before the magistrate court in Surajpur, naming 15 people, including a minor, in connection with the



subsequently transferred to the fast-track court in April 2016. The statement of Akhlaq's daughter, Shaista, was recorded on August 3, 2016, during the evidence stage of the trial.

On October 15, this year, the UP government filed an application under Section 321 of the Criminal Procedure Code seeking to withdraw all charges against the accused, citing changes in witness statements and evidentiary issues.

The application by Brajesh Kumar Mishra, Joint Director Prosecution, Gautam Buddha Nagar, seeking to withdraw the case read: "Both the complainants and the accused are residents of the same village, Bisada... Despite that, the complainant (Akhlaq's wife) and other witnesses (Akhlaq's son and daughter) have changed the number of accused in their statements."

lynching. However, the chargesheet did not specifically mention beef, as the final forensic report was not available at the time. The case was taken up by the sessions court on February 9, 2016, and

Persian carvings, Kashmiri woodwork: Delhi to get its very own houseboat along Yamuna

New Delhi.(Agency)

A houseboat in Delhi along Yamuna?

Residents may soon have an option to host meetings, conferences and small dining events in the heart of the city in a houseboat, typically found in Kerala and Jammu and Kashmir, with the DDA preparing to float tenders for a new convention centre at Baansera Park, a spokesperson for the Lieutenant Governor's Office said.

"The ambitious project is a part of initiatives undertaken by L-G VK Saxena, who has been pushing for development of the Yamuna floodplain as a public space for citizens to bring the people closer to the river, in the process, making their direct stakeholders in its cleaning and rejuvenation," the spokesperson said.

The structure, though designed like a houseboat, will be permanently fixed to the ground and will not float. The houseboat convention centre will be made of biodegradable timber and will not use concrete or steel. This is to ensure sustainability along the Yamuna floodplain.

The facility is expected to offer a meeting space for 15-20 people, a reception area with a waiting lounge, dining space with an attached pantry, gallery space, and interiors that match Kashmiri-style woodwork, including carved jail patterns and railings. The DDA expects the structure to have a lifespan of about 50 years, the spokesperson said. The DDA expects the work to be completed within 180 days of awarding the contract, with the planned completion timeline falling between May and June next year.

At roughly 9 m high, the houseboat will have multiple levels, including lower, ground, middle and upper decks. The spokesperson said the base will use deodar wood, while the superstructure will be made of cedar featuring walnut carvings. Interior wall panels and ceilings will use chinar wood. "The idea is to create a structure crafted by master artisans, with detailing inspired by traditional Kashmiri woodwork," the spokesperson added.

According to the project details shared by the L-G's Office, the houseboat will be located near the existing eatery at Baansera. All visible elements—including railings, columns, Mehraab arches and external panels—will feature Persian-style carvings. Windows will be made of cedar wood with carved sash designs fitted with glass panes. Each piece of timber will be seasoned to avoid warping, and natural resin or suitable all-weather sealants will be used to ensure structural longevity.

NEWS BOX

Afghan polio survivor's sock factory provides hope by employing disabled workers

HERAT. (Agency)

In a tiny room in the center of Herat, Afghanistan's westernmost city, Shahabuddin uses his hands to propel himself along the floor to a freshly-made pile of socks waiting to be sorted and packaged. A double amputee since a roadside bomb took both his legs a decade ago, when Afghanistan was mired in conflict between U.S.-led forces and Taliban insurgents, the 36-year-old father of four had struggled to find work. Unemployed for the last decade, he had been forced to rely on relatives for his family's survival. But a new sock production workshop in Herat employing only disabled workers has given him new hope. "I became disabled due to the explosion. Both my legs were amputated," Shahabuddin, who like many Afghans goes by only one name, said during a brief pause in his work in early December. "Now I work here in a sock factory, and I am very happy that I have been given a job here." The workshop is the brainchild of Mohammad Amiri, 35, a former grocery shop worker who started the business about a month ago. Amiri, himself disabled by childhood polio, wanted to create jobs and help provide income for other people with disabilities, particularly as many of them were injured during the conflict and have no other means of income. He teamed up with another polio survivor to start the sock factory with a workforce of men disabled either through traumatic injuries or because of congenital issues or other reasons. They make four types of socks: long and short, for winter and summer. "The factory, which is funded and supported by people with disabilities, began operations last month and currently employs around 50 people with disabilities," Amiri said. "They are busy in the production, packaging and sale of socks in the city." A combination of decades of conflict, a weak health care system and struggling economy have contributed to high levels of disability in Afghanistan. Data from a 2019 Model Disability Survey conducted by The Asia Foundation nonprofit organization indicates that nearly 25% of adults live with a mild disability, while 40% have moderate and about 14% have severe disabilities.

Hong Kong's pro-democracy media tycoon Jimmy Lai's national security trial verdict on December 15

HONG KONG. (Agency)

Hong Kong pro-democracy media tycoon Jimmy Lai will receive the verdict in his national security trial on December 15, a court website showed. Lai, who turned 78 this week, is charged with foreign collusion under Hong Kong's national security law, which Beijing imposed following huge and sometimes violent pro-democracy protests in 2019. The founder of the Apple Daily newspaper has been behind bars since late 2020, reportedly in solitary confinement, with Western nations and rights groups calling for his release. Lai's case is scheduled for a 60-minute hearing "for verdict" before a three-judge panel at 10 am (0200 GMT) on Monday, according to a court diary item seen on Friday. Aside from the collusion offence -- which could land him in prison for life -- Lai is also charged with "seditious publication", with prosecutors citing 161 items including op-eds with Lai's byline. Hong Kong authorities have repeatedly rejected criticism related to Lai, saying that his case was "handled strictly on the basis of evidence and in accordance with the law". During his trial, which began in December 2023, Lai denied calling for sanctions against China and Hong Kong as a whole and said he never advocated separatism or violent resistance. "The core values of Apple Daily are actually the core values of the people of Hong Kong... (including) rule of law, freedom, pursuit of democracy, freedom of speech, freedom of religion, freedom of assembly," Lai said in his testimony. Lai is a British citizen, and his son Sebastien voiced new concerns last week over the mogul's health.

"1 H-1B Worker Equals 10 Illegal Aliens": US Pollster's "De-Indianise" Call

World . (Agency)

Mark Mitchell, a leading US commentator and pollster, stirred a row after suggesting that major US firms should "de-Indianise" themselves. He said he wants to launch a consultancy to help corporations with the process. His remarks, posted on X, have sparked social media discussion about the role of Indian professionals in America's technology sector. "I have never in my life wanted anything more than this: to build a new corporate consultancy helping major firms de-Indianise," Mitchell posted. The statement came days after Mitchell, the head pollster at Rasmussen Reports, criticised the growing number of Indian professionals in the United States under the H-1B visa programme during a podcast. Attack On H-1B Visa Speaking at 'The War Room' podcast with Stephen Bannon, Mitchell hit out at Indian dominance in the H-1B visa programme and said sending back a senior H-1B developer working at top firms like Apple was economically the same as deporting ten illegal aliens. "But for every single H-1B, you know, senior developer at Apple that we send back, that's the equivalent economically, probably, of deporting ten illegal aliens. So, I don't know why we didn't do that yesterday. And the idea, yes, a lot of these people are entry level, but a lot of them are making a tonne of money," he said in a podcast released on December 8. The American pollster claimed 12 million American tech workers were left jobless because the "foreign-born workforce" has 'indicated' Silicon Valley.

Bangladesh's ex-PM Khaleda Zia placed on ventilator support: Doctors

The Bangladesh Nationalist Party (BNP) chairperson has been undergoing treatment at Dhaka's Evercare Hospital since November 23 for multiple health complications.

DHAKA. (Agency)

Former Bangladesh prime minister Khaleda Zia's health condition has deteriorated and she was placed on ventilator support, doctors said. "Her breathing difficulties increased, her oxygen level fell, and carbon dioxide levels rose," according to a statement on Thursday by the chief of the medical board cardiologist Shahabuddin Talukdar. It said the 80-year-old former premier was previously being treated with High Flow Nasal Cannula and BiPAP support, but as there was no improvement, she was placed

on elective ventilator support to give rest to her lungs and other vital organs. "The Bangladesh Nationalist Party (BNP) chairperson has been undergoing treatment at Dhaka's Evercare Hospital since November 23 for multiple health complications. The statement said the three-time premier was kept under round-the-clock medical watch by a team of local and foreign specialists, as several of her vital organs continue to be under severe stress. Her kidney function has stopped completely, and she is undergoing regular dialysis," the board said, adding she currently needed blood transfusions. The board detected problems in her "aortic valve" as well. "As her fever persisted and echocardiography showed issues in the aortic valve, a Transoesophageal Echocardiogram (TEE) was performed. It confirmed infective endocarditis, a serious



infection of the heart valve. Treatment for this has been started according to international guidelines," the statement read. It said that on November 27, the doctors detected her "acute pancreatitis" while Zia was being administered high-quality anti-biotic and anti-fungal drugs for "severe infections". Her personal physician and BNP standing committee member AZM Zahid Hossain has briefed the media on her health several times,

but this is the first time the medical board has issued a statement detailing her condition. In its statement, the board urged people not to circulate speculation or misinformation about Zia's condition and to respect her privacy and dignity. "Our medical team is working with the highest level of care, attention and sincerity." Zia was hospitalised on November 23 after she developed a chest infection that affected both her heart and lungs, and four days later, she was shifted to the coronary care unit (CCU) after several of her health complications worsened. She was scheduled to be flown to London last week with the medical board's consent but her scheduled departure was delayed as an air ambulance offered by Qatar could not reach Dhaka. The doctors later decided the former premier should receive continued treatment at the Evercare Hospital until she was deemed fit for the flight.

Japan issues tsunami advisory after 6.7 magnitude quake in country's northeast

KATHMANDU. (Agency)

Japan on Friday issued a tsunami advisory after a 6.7 magnitude earthquake shook the country's northeast, according to the Japan Meteorological Agency. The quake occurred off the east coast of Aomori prefecture, in the north of Honshu, the main Japanese island, at a depth of 20 kilometers (12.4 miles) at 11:44 a.m. local time, JMA said. The Pacific coast of Hokkaido, Aomori, Iwate and Miyagi prefectures could see a tsunami of up to 1 meter (3.2 feet), the agency added. Damage and injuries weren't immediately clear. An advisory is a lower level of caution than a warning.

Friday's quake followed a 7.5 magnitude earthquake earlier this week in the north that caused injuries, light damage and a tsunami in Pacific

coastal communities. At least 34 people were injured in that quake on Tuesday morning.



Monday off the coast of Aomori, the northernmost prefecture of Japan's main Honshu island.

A tsunami more than 2 feet (0.6 meters) above tide levels was measured in Kuji port in Iwate prefecture before all tsunami advisories were lifted. Power was knocked out for hundreds of

homes but was mostly restored Tuesday morning.

Authorities had warned of possible aftershocks. Officials said after Monday's quake there was also a slight increase in risk of a magnitude 8-level quake and possible tsunami occurring along Japan's northeastern coast from Chiba, just east of Tokyo, to Hokkaido.

The agency urged residents in 182 municipalities in the area to monitor their emergency preparedness in the coming week, reminding them that the caution is not a prediction of a big one.

The quakes occurred in the coastal region, where a magnitude 9.0 quake and tsunami in 2011 killed nearly 20,000 people and destroyed the Fukushima Daiichi nuclear power plant.

Myanmar military strikes a hospital in a rebel-controlled area, killing 34 and injuring 80 people

BANGKOK. (Agency)

An airstrike by Myanmar's military destroyed a hospital in an area controlled by a leading rebel armed force, killing 34 patients and medical staff, according to a rescue worker and independent media reports Thursday. About 80 other people were injured in the attack Wednesday night on the general hospital in Mrauk-U township, an area controlled by the ethnic Arakan Army in the western state of Rakhine. The military, which took over Myanmar's government in 2021 and has been fighting ethnic militias and armed resistance forces since then, has not mentioned any attack in the area. Wai Hun Aung, a senior official for rescue services in Rakhine, told The Associated Press that a jet fighter dropped two bombs at 9:13 p.m. with one hitting the hospital's recovery ward and the other landing near the hospital's main building. He said he arrived at the hospital early Thursday to provide assistance and recorded the deaths of 17 women and 17 men. He said that most of the hospital building was

destroyed by the bombs, and taxis and motorbikes near the hospital were also damaged. Rakhine-based online media posted photos and videos showing damaged buildings and debris



including medical equipment. The hospital has been the main source of health care for people in Rakhine, where most hospitals have closed because of Myanmar's civil war, said Wai Hun Aung. It was reopened after doctors gathered in Mrauk-U to provide much-needed medical services. Mrauk-U, located 530 kilometers (326 miles) northwest of Yangon, the country's largest city, was captured by the Arakan Army in

February 2024. The Arakan Army is the well-trained and well-armed military wing of the Rakhine ethnic minority movement, which seeks autonomy from Myanmar's central government. It began its offensive in Rakhine in November 2023 and has seized a strategically important regional army headquarters and 14 of Rakhine's 17 townships. Rakhine, formerly known as Arakan, was the site of a brutal army counterinsurgency operation in 2017 that drove about 740,000 minority Rohingya Muslims to seek safety across the border in Bangladesh. There is still ethnic tension between the Buddhist Rakhine and the Rohingya.

Myanmar's shadow National Unity Government, established by elected lawmakers who were barred from taking their seats in 2021, condemned the airstrike. The organization urged the international community to pressure the military to end its actions, take action against perpetrators and provide humanitarian assistance as soon as possible.

Thailand's Parliament dissolved ahead of new elections early next year

BANGKOK. (Agency)

Thailand's Parliament was dissolved Friday for new elections early next year in a country engaged in deadly fighting with Cambodia.

Prime Minister Anutin Charnvirakul dissolved the House of Representatives after getting approval from King Maha Vajiralongkorn, whose endorsement became effective Friday with its publication in the Royal Gazette. Anutin had signaled the move with a Facebook post late Thursday saying: "I'd like to return power to the people." The election must be held 45 to 60 days after the royal endorsement, a period during which Anutin will head a caretaker government with limited powers that cannot approve a new budget.

His action comes at a tricky political moment, as Thailand is engaged in large-scale combat with Cambodia over long-disputed border claims. About two dozen people were reported killed in the fighting this week, while hundreds of thousands have been displaced on both sides. Anutin has been prime minister for just three months, succeeding Paetongtarn Shinawatra, who served only a year in office.

Anutin won the September vote in Parliament with support from the main opposition People's Party in exchange for a promise to dissolve Parliament within four months and organize a referendum on the drafting of a new constitution by an elected constituent assembly. The party, which runs on progressive platforms, has long sought changes to the constitution, imposed during a military government, saying they want to make it more democratic. The issue of constitutional change appeared to trigger the dissolution, after the People's Party prepared to call a no-confidence vote Thursday. That threat came after lawmakers from Anutin's Bhumjaitai Party voted in favor of a bill to amend the constitution that the opposition party felt ran against the spirit of the agreement they had reached in September.

The People's Party holds the largest number of seats in the House of Representatives and is seen as the main challenger to Bhumjaitai. As news of the pending dissolution circulated late Thursday, its leaders said they hoped Anutin would still honor the agreement to arrange a constitutional referendum. Anutin had served in Paetongtarn's former government but resigned from his positions and withdrew his party from her coalition government in June in the wake of a political scandal related to border tensions with Cambodia. Paetongtarn, daughter of former Prime Minister Thaksin Shinawatra, was suspended from office in early July after being found guilty of ethics violations over a politically compromising phone call with Cambodia's Senate President Hun Sen ahead of July's armed conflict.

China's new 'condom tax' draws skepticism and worries over health risks

SURIN. (Agency)

China will soon start collecting a value-added tax on contraceptive drugs and products for the first time in over three decades, a move aligned with Beijing's effort to get families to have more children after decades of limiting most to one child. "Contraceptive drugs and products" will not be tax-exempt as of Jan. 1, according to the country's newest value-added tax law. Products such as condoms will be subject to the usual 13% value-added tax imposed on most products. While state-run news outlets have not widely highlighted the change, it has been trending on Chinese social media, drawing ridicule among people who joked they'd have to be fools not to know that raising a child is more expensive than using condoms, even if they are taxed. More seriously, experts are raising concerns over potential increases in unplanned pregnancies and sexually transmitted diseases due to higher costs for contraceptives. The ruling Communist Party's past "one-child" policy was enforced from about 1980 until 2015 with

huge fines and other penalties and sometimes with forced abortions. In some cases, children born over the limit were deprived of an identification number, effectively making them non-citizens. The government raised the birth limit to two children in 2015. As China's population began to peak and then fall, it was lifted to three children in 2021. Contraception has been actively encouraged and easily accessed, even for free. "That's a really ruthless move," said Hu Lingling, mother of a 5-year-old who said she is determined not to have another child. She said she would "lead the way in abstinence" as a rebel. "It is also hilarious, especially compared to forced abortions during the family planning era," she said.

In 2024, 9.5 million babies were born in China, about one-third fewer than the 14.7 million born in 2019, according to the National Bureau of Statistics. That's despite a higher-than-usual birth rate driven by a traditional preference to give birth in the Year of the Dragon, according to Chinese astrology.

As deaths have outpaced births in China, India overtook it as the world's most populous country in 2023. The effect of the



tax "on encouraging higher fertility will be very limited. For couples who do not want children or do not want additional children, a 13% tax on contraceptives is unlikely to influence their reproductive decisions, especially when weighed against the far higher costs of raising a child," said Qian Cai, director of the Demographics Research Group at the University of Virginia. Still, imposing the tax is "only

logical," said Yi Fuxian, a senior scientist at the University of Wisconsin-Madison.

"They used to control the population, but now they are encouraging people to have more babies; it is a return to normal methods to make these products ordinary commodities," Yi said. As is true in most places, most responsibility for birth control in China falls to women. Condoms are used by only 9% of couples, with 44.2% using intrauterine devices and 30.5% female sterilization, followed by 4.7% male sterilization, according to research released by Bill & Melinda Gates Foundation in 2022.

The rest use the pill or other methods. Given the authorities' longstanding invasive approach to their personal lives and bodies, some women are offended by the authorities' effort to again influence their personal choices about childbearing. "It is a disciplinary tactic, a management of women's bodies and my sexual desire," said Zou Xuan, a 32-year-old teacher in Pingxiang in China's southern province of Jiangxi.

NEWS BOX

Idolising Virat Kohli, Nikhil Chaudhary dreams IPL stint with RCB legend

NEW DELHI . (Agency)

When Nikhil Chaudhary walked onto the field for Punjab in 2017, Virat Kohli was at the height of his powers, dominating cricket across all formats. Nine years on, while Kohli approaches the twilight of his illustrious career, Chaudhary's journey has taken a very different trajectory—one that has led him far from India, to a new life in Australia.

For Chaudhary, Kohli has always been more than just a cricketer—he's an idol. And now, in a twist of fate, there's a chance he could line up alongside him in the upcoming Indian Premier League (IPL). Registered as a local player in the mini-auction, the 29-year-old dreams not just of an IPL contract but of sharing a dressing room with his childhood hero. The story of how Chaudhary landed in Australia is almost cinematic. In 2020, a simple visit to relatives became an unexpected turning point. Stranded due to the Covid-19 pandemic, he found himself staying longer than planned—and gradually, he made Australia his home. From representing Tasmania to pulling on the



jersey of the Hobart Hurricanes in the Big Bash League, Chaudhary has carved a niche for himself far from the land of his birth. But success didn't come overnight. Chaudhary's early days in Australia were a grind. He delivered letters for Australia Post, drove for Uber, and even chopped vegetables in a Brisbane restaurant before his cricketing break arrived. The contrast with his early career in Punjab—sharing dressing rooms with Abhishek Sharma and Arshdeep Singh—couldn't have been starker. Now, with 20 BBL matches and stints in the Syed Mushtaq Ali Trophy to his name, Chaudhary is ready for the next step. The 2025-26 season could be the one where he stakes a claim in first-class cricket. In the ongoing Sheffield Shield, he has already amassed 367 runs at an average of 45.87, including a stunning 163 against New South Wales that has caught the eyes of selectors. And he's more than just a batter—his leg-spin has yielded a first-class five-wicket haul, adding another dimension to his game. India Today Digital caught up with Chaudhary recently.

Is Gautam Gambhir's fixation on Shubman Gill threatening India's T20 World Cup defence

New Delhi. (Agency)

For months now, the most animated debate around India's T20I setup has centered on one deceptively simple question: who should open with Abhishek Sharma? The left-hander has sealed his spot with commanding form and unwavering intent, yet the identity of his partner remains a point of national contention. As things stand, vice-captain Shubman Gill continues to be the preferred choice, even as Sanju Samson, the man with three T20I hundreds in 2024, watches from the periphery.

To understand how head coach Gautam Gambhir has arrived at this decision, one might need more than selectorial instinct; perhaps an algebraic equation would explain why he remains wedded to an out-



of-form opener less than two months before a World Cup. The Gill question has loomed large over Indian cricket since the summer, yet Gambhir has shown little inclination to entertain the logic or statistics that stand firmly against his chosen man. Samson's case is straightforward and compelling. Not many players produce three T20I centuries across an entire career, and Samson did it in a single year. His synergy with Abhishek at the top was one of India's most exciting developments in 2024. But come the 2025 Asia Cup, he found himself displaced, pushed down to the lower middle order, and eventually benched. None of those roles suits his game or reflects the kind of form he has shown.

Gill's slump raises hard questions

Gill, meanwhile, has retained his place without producing the returns that justify such unwavering support. Thursday's golden duck against South Africa in Mullanpur was the latest addition to an uncomfortable pattern. He now has no fifty in his last 17 T20I innings. His struggles against Lungi Ngidi only deepened the sense of concern, as he has now been dismissed twice in three balls across the series.

Bazball is great, but England go too far with it sometimes: David Willey

David Willey believes England's Bazball approach is innovative but warns that players must adapt to situations, especially as England trail Australia 0-2 in the Ashes. Willey highlights missed opportunities and calls for accountability and refinement in England's strategy.

BRISBANE. (Agency)

Former England international and current Dubai Capitals all rounder David Willey has called for a more measured approach to England's Bazball style, warning that while the aggressive brand of cricket has been transformative, it can overshadow crucial match situations if not tempered. England currently trail Australia 0-2 in the five-match Ashes Test series, with both defeats exposing moments where game management may



have faltered. Willey acknowledged the excitement Bazball has brought to English cricket but stressed the need for players to adapt to the flow of the match. He noted that Ben Stokes has recognised this and expects the team to refine their approach for the rest of the series. "I think the term 'Bazball' is something that's been used more by the media than the players themselves. They're trying to impact the game, but I have my reservations about maybe going too far that way and not taking accountability for when the game dictates something else. The way Stokes talked about it, he's really highlighted

that. I've no doubt they'll be trying to refine that and put that right for the remainder of the series," Willey was quoted as saying by ANI. England's aggressive intent was evident during the Ashes, where they suffered consecutive eight-wicket defeats. In the first Test at Perth, England appeared steady at 76-3, only to lose seven wickets for 88 runs and be dismissed for 164. Willey said England missed crucial moments in both Tests, and better batting in key situations could have changed the outcomes. He believes the team needs to recognise when to absorb pressure instead of always playing aggressively.

"If you look back to Perth, if they'd have batted better in that third innings, there's every chance they could have won that test match and everyone would be sat having different conversations now. And the same again in the second test, there are just key moments where England let them slip and that's ultimately cost them. So I think they'll be really trying to identify those moments and know when to potentially absorb a little pressure and just dig in a little bit rather than play the expansive style of cricket they want," Willey said.

The defeats highlighted the fine line between positive play and recklessness, with England's aggressive philosophy drawing massive scrutiny from the cricketing fraternity. Willey suggested that being able to "absorb a little pressure and just dig in" might be key to success in tighter contests. As England prepare for the remaining Ashes matches, Willey expressed confidence in the team's leadership under Ben Stokes to make necessary adjustments. He expects England to assess their approach and strike a better balance between aggression and situational awareness as they head into third Test scheduled to be played in Adelaide beginning on December 17.

Teenagers set Finnish football stadium ablaze after club suffers relegation

New Delhi. (Agency)

A shocking fire at FC Haka's historic Tehtaan kenttä stadium has left one of Finland's oldest football venues severely damaged, just weeks after the club was relegated from the country's top league, Veikkausliiga. The blaze erupted on December 7, Sunday evening in Valkeakoski and completely destroyed a 400-seat wooden stand, sending ripples through a community already reeling from sporting disappointment. Police later confirmed that three minors were present at the scene when the fire began, all of them under the age of 15. One teenager has admitted to igniting an object that sparked the inferno, though Finnish law prevents anyone under 15 from facing criminal charges. Speaking in a statement, Detective Inspector Majajärvi Tammisto said the case is being investigated as arson but clarified that legal consequences differ for minors. While criminal prosecution is off the table due to age, she noted that compensation liability can still apply to

children in Finland. "The police hope that discussion about the matter remains appropriate and reminds people that in appropriate and personal communications can themselves lead to a



criminal investigation," Tammisto said. Tammisto also urged restraint as the incident triggered angry reactions online. She reminded the public that hostile or personal comments on social media could themselves become subject to criminal investigation, particularly if they target identifiable minors.

The fire broke out around 8 PM and rapidly spread through the wooden structure of the nearly century-old stand. Built in 1934, Tehtaan kenttä—known in English as Factory Field—has long been considered one of Finnish football's most traditional grounds. FC Haka chairman Marko Laaksonen said the extent of the damage has not yet been calculated but is expected to be substantial. With the club already coping with the financial and emotional fallout of relegation, the timing of the incident has made the setback even heavier. "We certainly didn't need this... We have already received a lot of support from people and we will continue to need it in the future," Laaksonen told Finnish media.

The stadium is owned by the city of Valkeakoski, whose council chairman Joni Kuulander expressed sadness at the destruction and pledged swift action to restore the pitch and facilities. Preparations are now underway to assess what it will take to make the venue playable again.

Pep Guardiola praises Real Madrid's Rodrygo amid rising Manchester City transfer buzz

Madrid. (Agency)

Pep Guardiola has coached against some of the world's finest attackers, but even he couldn't hide his admiration for Rodrygo Goes after Manchester City's 2-1 win over Real Madrid at the Santiago Bernabeu. On a night shaped by City's resilience, Madrid's mounting problems, and Rodrygo's reminder of his brilliance, it was Guardiola's reaction to the Brazilian that sparked renewed chatter in the transfer market. City's victory, secured through goals from O'Reilly and Erling Haaland, overshadowed Rodrygo's sharp finish—a moment of individual quality that immediately caught Guardiola's eye. And with Rodrygo having been linked heavily with Manchester City in the previous transfer window, his standout performance came with extra intrigue. Speaking to Movistar+ after the match, Guardiola delivered unusually glowing praise, moments after sharing a brief on-field

exchange with the winger. "I told Rodrygo how good he is. He's a player from another level this kid is a player on



another level. I'm glad he's back from injury. He's very, very good." Rodrygo's goal ended a 281-day drought, his last coming on March 4, 2025, and it arrived at a time when Madrid desperately needed a spark. Instead, the night concluded with another setback for Xabi Alonso's side,

who remain five points behind Barcelona in LaLiga and continue to slide in Europe. Amid the on-field drama, Rodrygo's future remains a talking point. Manchester City were the last club to formally pursue the Brazilian, and the transfer talks have heated up during Rodrygo's limited involvement in Xabi's Real Madrid plans this season. Their approach last summer stalled only because Rodrygo opted to stay in Madrid, believing it was not the right moment to move. Guardiola's praise, however, has naturally reignited speculation about whether City might revisit that interest.

Madrid's current struggles have put Alonso under increasing scrutiny, though senior players including Rodrygo, Thibaut Courtois and Jude Bellingham have publicly backed him. Still, the noise surrounding Rodrygo's role and future refuses to quieten.

Shubman, Suryakumar's form not a concern, they'll come good soon: Assistant coach

New Delhi. (Agency)

India assistant coach Ryan ten Doeschate has defended T20I captain Suryakumar Yadav and vice-captain Shubman Gill amid their poor form in the format. Both Gill and Suryakumar continued their dry patch in the second T20I against South Africa in Mullanpur, getting dismissed for 0 and 5 respectively as India failed to chase down the massive target of 214 and lost by 51 runs. The duo has had a long run of low scores in the format, which is an alarming sign for the Men in Blue heading into the T20 World Cup 2026, scheduled to be held in India from February 7 to March 8. Despite their poor run, ten Doeschate feels the lack of runs from



their bats is not a huge concern and backed the batting stalwarts to come good soon. He defended Shubman mentioning that he got a great delivery from Lungi Ngidi in Mullanpur and had been dismissed while attacking in the first T20I in Cuttack. "Shubman, I saw some good signs of a change in mentality on the back end of that Australian tour. I wouldn't read too much into these two dismissals in this series. In the first game, we asked the guys to go out there and attack the powerplay, and it wasn't a great wicket at Cuttack, so I'll let him off for that one. Today, I thought he got a good ball that can happen when you're short on form," said ten Doeschate in the post-match press conference. Ten Doeschate also said that both Suryakumar and Gill deserve strong backing from the team management given their class, and he brushed off any concerns regarding their form. "But we also know his class. You look at his IPL record, he stacks up 700-800 runs. We believe in his class, and we believe he will come good. It's exactly the same with Suryakumar.

What wrong has Sanju Samson done Uthappa wants Shubman Gill replaced as T20I opener

Robin Uthappa called out India's decision to drop Sanju Samson from the opening slot in T20Is. With Shubman Gill struggling, his criticism has put fresh spotlight on India's T20I selection.

WELLINGTON. (Agency)

Shubman Gill's ongoing struggles in T20Is have intensified scrutiny on India's selection calls, especially after his golden duck in the second T20I against South Africa in Mullanpur. Chasing a daunting 214, Gill lasted just one ball, beaten by Lungi Ngidi's movement and dismissed at first slip. The moment not only jolted India early in the chase but reopened a debate that has dominated discussions for months: why does Gill continue to open despite a prolonged

slump, while Sanju Samson remains sidelined? The frustration stems from the stark contrast in form and opportunity. Samson, who smashed three T20I hundreds in 2024 and developed a potent partnership with Abhishek Sharma, now finds himself pushed out of the XI. Meanwhile, Gill has been repeatedly backed, even as his returns at the top have dipped steadily. With the T20 World Cup inching closer, the decision to persist with Gill has raised questions about whether India are prioritising hierarchy over performance. Speaking on Star Sports after India's crushing defeat in the Mullanpur T20I on December 11, Robin Uthappa voiced what many Indian fans have wondered: what wrong has Sanju Samson done to deserve this treatment? He questioned why a successful opening pair was dismantled without a convincing explanation from the team management. "I beg the question: what did the partnership of Abhishek Sharma and Sanju Samson do so grossly wrong that they



had to be replaced? I understand Surya in the pre-series conference where he said Shubman has actually been in the T20 squad before Sanju got his opportunity. But when Sanju did get his opportunity, he got three hundreds. He was the first guy among the youngsters here to get hundreds in T20 cricket. It was after that when Abhishek got it, and after that when Tilak actually got it. So he perhaps even inspired the guys and challenged them, because at that point, they were figuring out who was going to be the next opener for India in T20 cricket,"

Uthappa said. "So you have a proven opener, who's averaging just below Abhishek Sharma at this point, and you decided to move him to the middle order and then slowly leave him out. What wrong has he done? Is my question. He deserves to have that opportunity," he added. He was equally blunt in his assessment of Gill's current approach, and emphasised and on what is going wrong for the Test and ODI skipper in T20Is. "It's not working for Shubman at this point, because I also think he's trying different things. I think he's trying initially to go toe-to-toe at the same pace that Abhishek is going—that is not how he bats. That is not how he's been successful in T20 cricket. How he has been successful is by taking that time, those first 10 balls, absorbing the pressure, getting in, and then once he reaches 15-20 balls, I don't think there is a batter like Shubman Gill until he gets himself out. That's the kind of batter he is. And I think that's what works for him in T20 cricket," Uthappa said.

Alia Bhatt

Looks Stunning In Floral Gown As She Accepts Award At The Red Film Festival

In the pictures posted online, Alia is seen wearing an exquisite strapless, floor-length gown featuring a sweetheart neckline and a beautifully draped bodice. The outfit showcases a soft sandy base embellished with large, pastel-toned floral embroidery in shades of pink, blue and yellow. A delicate sheer cape cascading from one side adds movement and sophistication to the ensemble. Her hair is styled in loose, soft waves tucked behind one ear, paired with muted, polished makeup. With minimal jewellery, Alia allowed her intricately designed gown to remain the highlight of her look. Alongside the pictures, she wrote, "a gentle reminder of why I love cinema... its power to bridge horizons Honoured to receive the Red Sea Film Golden Globe Horizon award."

Alia Bhatt Delivers Empowering Speech for Young Dreamers

During the ceremony, the actress took the stage to express her gratitude and share a heartfelt message for young girls with big dreams. In her speech, she said, "I stand here today as truly grateful 5-year old that I got to live my dream and I just want to talk to every girl out there who perhaps feels that her dream is too big or too large or too unachievable. The thing I would say from the little time that I have been working is never shrink your dream to fit in anyone else's reality. Just hold on to it long enough to show up and do the work everyday and chase the horizon no matter wherever it takes you."

She further added, "This is an honour to be recognised by the Golden Globes and I am grateful for the opportunity to speak for a new generation of aspiring performers and women who are making a difference in film and television around the world." The evening also celebrated Tunisian actor Hend Sabry, who was honoured with the Omar Sharif Award. Fans and Celebrities Shower Alia With Praise Soon after Alia shared the pictures, the comments section was flooded with congratulatory messages from fans and colleagues. Her mother-in-law Neetu Kapoor wrote, "Loveee it," while actor Hrithik Roshan added, "Beautiful pics."

What's Next for Alia Bhatt?

On the work front, Alia Bhatt is gearing up for her next major project, *Love and War*, directed by Sanjay Leela Bhansali. The highly anticipated film also stars Ranbir Kapoor and Vicky Kaushal in lead roles. While an official announcement is awaited, reports suggest that the film is targeting a March 20, 2026, theatrical release.



Malaika Arora 'Tries Hard' To Shield Her No-Makeup Morning Face, But Fails



Malaika Arora is a true-blue fashionista, and there's no second thought in it. The one thing she loves to do is hit the gym right in the morning. Don't believe us? The actress was seen rushing to her car while wearing gym attire to shield her early-morning, no-makeup appearance. In a video posted on Instagram, Malaika Arora was papped while exiting her residence early this morning. She was captured wearing her gym athleisure, which included an oversized hoodie jacket paired with a pair of loose-fitted pants. The actress was also seen carrying a black duffel bag that appeared to be filled with her gym essentials.

Malaika Arora's Fans Call Her 'Cutie'

On the other hand, the 52-year-old finished off her appearance with absolutely no makeup and a pair of white sneakers. She back-brushed her hair in a messy yet sleek bun at the back, adorned with a huge clutch. But soon after, she was spotted by paparazzi stationed there, and the actress rushed to her car to keep her natural look out of view. The video's caption read, "A quick glimpse of the diva #malaikaarora is the best thing to happen to everyone this morning." Soon, social media users flooded the comment section with their various reactions. A fan said, "Always gorgeous." Another called her "cutie". Other comments read, "Morning mood," "My mom wants to be like you, she is your fan," "Pretty girl," and more.

Malaika Arora's Appearance In Dubai

The Chaiyya Chaiyya actress captivated audiences with an electrifying stage performance at the grand launch of Shalrukhz by Danube, a premium commercial tower named after superstar Shah Rukh Khan. Dressed in a sheer, crystal-encrusted bodysuit, Malaika took no time to capture the spotlight with her magnetic performance. Her moves can give many youngsters a run for their money, and the credit goes to her rigorous fitness regimen.

Hema Malini Gets Emotional Remembering Dharmendra At Prayer Meet: 'Humein Ek Hit Pair Ke Roop Mein...'



Veteran actor Dharmendra, the He-Man of Bollywood, passed away on November 24. Weeks after his demise, his second wife and actress Hema Malini hosted a prayer meet in his memory in New Delhi. During the prayer meet, Hema, joined by her two daughters Esha and Ahana Deol, spoke about Dharmendra and the king-size life that he lived. Addressing the guests at the prayer meet ceremony, Hema said, "He was cheerful and affectionate; even while standing at the peak of fame, he never considered himself different from others, he always remained grounded. He spoke to people of every background with immense love, affection, and respect. Such a person was Dharam ji."

"Dharmendra ji se mera association 57 saal ka hai. Jab main film industry mein aayi tab se mujhe unke saath zyada tar film mein karne ka avasar mila. Nearly 45 films—we worked together. Hum dono ko ek hit pair ke roop mein industry bhi pyaar karti thi aur janta ne bhi humein khoob pyaar diya," she continued while reminiscing about the old days when they shared the screen together.

Speaking about Dharmendra's career, Hema continued, "In his career, Dharmendra ji acted in more than 300 films and portrayed a wide range of roles, romantic, action hero, serious roles. But he used to love comedy the most. He was very passionate about films; he loved to be in front of the camera." Dharmendra would have turned 90 this year on December 8th, and speaking about how even after his demise not only the family but the entire nation celebrated him for the man he was, Hema added, "On the 8th of December, he turned 90. We celebrated his birthday, and the entire nation celebrated it as well. People were deeply emotional. Even today, people come to me and talk about him. It is rare for anyone to receive as much respect and admiration as Dharam ji has received. Sometimes I wonder how vast and extraordinary his life has been."

She concluded her speech by saying, "His life is a celebration. He has influenced so many people in the world and inspired countless others. The entire industry is mad about him."

Dharmendra passed away on November 24. Previously, his sons Sunny Deol and Bobby Deol also held a prayer meeting in Mumbai, which was attended by several Bollywood stars including Shah Rukh Khan, Salman Khan, Malaika Arora, Aishwarya Rai Bachchan, Abhishek Bachchan, Madhuri Dixit, Rekha, Jackie Shroff, and Suniel Shetty. Dharmendra's final on-screen appearance will be in *Ikki*, which is slated to release in theatres on December 25, 2025. Directed by Sriram Raghavan, the film also stars Agastya Nanda and Jaideep Ahlawat in pivotal roles.

Sobhita Dhulipala

Opens Up On Being Married To Naga Chaitanya For A Year: 'It's Been Blissful'



Sobhita Dhulipala, who married Naga Chaitanya in Hyderabad last year, reflected on completing one year of marriage and said the phase has been emotional and grounding. In an exclusive chat with News18 Showsha while promoting her partnership with *Aadyam*, the *Made in Heaven* actress shared that love, for her, comes from realising you are already complete on your own and a partner simply brings out the parts of you that already exist. In her wedding video that she shared to mark their first

anniversary, Sobhita said, "I don't know if I believe that a person is incomplete and somebody else comes in and fills that void. Because I think we are complete on our own. And yet, in his absence, I would not be full."



Announcing on the thought, she added, "I was feeling quite emotional, so I just spoke from that space at that time. It's a little bit like Carl Jung's theory. There are people who believe that we meet our soulmate or

they complete us. I don't think like that. I feel like we are complete on our own. Some people arrive at that feeling much earlier, some people take a while to realise that 'okay, I don't need someone to make me feel like this, it's within'.

But in that journey, while we reach there, I think there is a longing for someone — I guess someone who complements us, someone who's the yin to your yang or yang to your yin. And it's not like they come and like complete you, but through them you realise those parts of your personality. So in that longing is where I think a lot of love is born."

Life, she admitted, has busy after marriage. "I thought, after getting married I was going to chill for a bit and explore Hyderabad, but I have been shooting for two films. It's been over a 160 shoot days, so I've been mostly in Tamil Nadu for that. It's been exciting. Asked how they find time for each other amid busy schedules, Sobhita added, "If you like something, you like to do something, you will make it happen. And it will feel easy. If you don't like something, even the most convenient thing can feel like, 'oh, so tough'."

Asked how the past one year of being married to Naga Chaitanya has been, the actress smiled and said, "It's been blissful, great. I've been in a very, very inspired state creatively. I feel greatly empowered."

Naga Chaitanya was earlier married to actress Samantha Ruth Prabhu, who recently tied the knot with director Raj Nidimoru of *Raj & DK* fame.

